



डीहा

समस्या से समाधान तक

101

वर्ष-01 | अंक-06 | पाक्षिक | 16 से 31 अक्टूबर 2026 | मूल्य : 20 | पृष्ठ-12

भाजपा का 'मिशन छत्तीसगढ़': स्मृति ईरानी ने संभाला प्रदेश भाजपा का प्रभार, दो दिवसीय रायपुर दौरे पर लीं मैराथन बैठकें, नेताओं और मंत्रियों को दिया कड़ा संदेश



छत्तीसगढ़ की राजनीति में इस वक्त ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है। बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी ने रायपुर आते ही संगठनात्मक अनुशासन का वो हंटर चलाया है, जिसने बड़े-बड़े मंत्रियों और विधायकों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बंद कमरों में हुई गोपनीय बैठकों में स्मृति ईरानी किसी सख्त स्कूल प्रिंसिपल की तरह नज़र आईं, जहाँ मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड फटे, कड़ियों के चेहरे उतर गए और दिग्गजों की क्लास लग गई।

कौन हैं स्मृति ईरानी?

स्मृति ईरानी की राजनीतिक कार्यशैली को समझने के लिए उनका पुराना सफर जानना बेहद ज़रूरी है। राजनीति में कदम रखने से पहले वो ग्लैमर वर्ल्ड, फिल्मों और टीवी इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम थीं। मॉडलिंग से शुरुआत करने के बाद उन्होंने हिंदी और बंगाली फिल्मों में भी अभिनय किया। लेकिन उन्हें सबसे बड़ी पहचान छोटे पर्दे से मिली। टीवी सीरियल 'क्यूंकि सास भी कभी बहू थी' में 'तुलसी' का जो आइकॉनिक किरदार उन्होंने निभाया, उसने उन्हें देश के हर घर में एक बेहद लोकप्रिय और जाना-पहचाना चेहरा बना दिया। इसके बाद साल 2003 में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और दिल्ली की चांदनी चौक सीट से अपना पहला बड़ा चुनाव लड़ा। उनका सबसे ऐतिहासिक मुकाबला 2014 और 2019 में कांग्रेस के गढ़ अमेठी में राहुल गांधी के खिलाफ हुआ, जहाँ 2019 में राहुल गांधी को हराकर उन्होंने खुद को बीजेपी का सबसे बड़ा फायरब्रांड और कद्दावर नेता साबित कर दिया।

आखिर क्यों स्मृति ईरानी को बनाया गया छत्तीसगढ़ का प्रभारी?

बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा छत्तीसगढ़ में एक महिला प्रभारी को नियुक्त करने के पीछे बहुत गहरी राजनीतिक सोच है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में देखा जाए तो महिलाओं की भूमिका बहुत ही अहम मानी जाती है। प्रदेश में महिला वोटर्स किसी भी पार्टी की जीत-हार तय करने में सबसे बड़ी ताकत हैं। स्मृति

ईरानी को आगे करके बीजेपी का सीधा टारगेट प्रदेश की आधी आबादी यानी महिला वोटर्स और मातृशक्ति को पूरी तरह से अपने पाले में साधना है। एक महिला नेता और घरेलू चेहरा होने के नाते स्मृति ईरानी महिला कार्यकर्ताओं और आम महिलाओं से बहुत आसानी से और सीधे कनेक्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि वे आधी आबादी और महिला विंग को 2028 के चुनाव के लिए अभी से तैयार करने में जुट गई हैं।

इन दो योजनाओं के दम पर चुनाव जीतेगी बीजेपी?

अब बात करते हैं उस मुख्य रणनीति की जिसके दम पर बीजेपी 2028 के चुनाव का चक्रव्यूह रच रही है और जिसके लिए स्मृति ईरानी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। छत्तीसगढ़ में साथ सरकार दो सबसे बड़ी कल्याणकारी योजनाओं पर फोकस कर रही है, पहली 'महतारी वंदन योजना' और दूसरी 'पीएम आवास योजना'। आपने खुद गौर किया होगा कि साथ सरकार जब भी महतारी वंदन योजना की मासिक किश्त जारी करती है, तो उसके लिए बाकायदा अलग से बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हर एक जिले में उत्सव का माहौल होता है और मंच से बाकायदा एक-एक किश्त का ऐलान करके आक्रामक प्रचार-प्रसार किया जाता है ताकि जनता को पता रहे कि उन्हें सीधे लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही हर मंच पर 18 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को पक्का मकान देने के लिए पीएम आवास योजना का जिक्र भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों द्वारा लगातार किया जा रहा है। कयास यही हैं कि बीजेपी की चुनावी वैतरणी को पार लगाने में यही दो योजनाएं सबसे बड़ी रीढ़ साबित होने वाली हैं।

महतारी वंदन योजना कितने करोड़ खर्च कर रही सरकार

अगर इस महा-योजना के जमीनी आंकड़ों को समझें, तो छत्तीसगढ़ में कुल 68 लाख 52 हजार से ज्यादा महिलाएं इस योजना के तहत रजिस्टर्ड हैं। इनमें से हर महीने लगभग 67 लाख 38 हजार से ज्यादा महिलाओं के बैंक खातों में सीधे डीबीटी के जरिए 1,000 रुपये ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

सरकार हर महीने केवल एक किश्त जारी करने के लिए 632 करोड़ 40 लाख रुपये से ज्यादा की भारी-भरकम राशि जारी कर रही है और अब तक कुल 20,708 करोड़ रुपये से ज्यादा बांटे जा चुके हैं। लेकिन इस बीच करीब 1 लाख 14 हजार महिलाएं ऐसी भी हैं जिनका फॉर्म भरने के बाद भी पैसा अटक गया है, जिसका मुख्य कारण आधार लिंक न होना, बैंक खाते में गड़बड़ी या ई-केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग होना है। इसके अलावा जो महिलाएं अपात्र पाई गईं या जिनके सरकारी मापदंड मैच नहीं हुए, उनके नाम काट दिए गए हैं। स्मृति ईरानी इसी विशाल महिला वोट बैंक को 2028 के लिए अभेद्य किला बनाने की तैयारी में हैं।

ज़मीन में बैठकर क्यों सुनी 'मन की बात' क्या है संदेश?

बता दें कि स्मृति ईरानी का सिर्फ और सिर्फ यह ज़मीन में बैठकर 'मन की बात' सुनने का मकसद केवल एक था- लोगों को ज़मीन से जोड़ना और नेताओं को उनकी असलियत याद दिलाना। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अपने लिए कोई वीआईपी मंच या विशेष व्यवस्था स्वीकार नहीं की, बल्कि वो खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के साथ साधारण कार्यकर्ताओं के बीच ज़मीन पर बैठ गईं। जब कुछ बड़े पदाधिकारियों ने उनके ठीक पीछे बैठने की जगह बनाई, तो स्मृति ने उन्हें दो ठूक शब्दों में डांटकर पीछे भेज दिया और कहा कि बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को सबसे सामने बैठने दिया जाए। यह सीधे तरीके से उनके व्यवहार को दर्शाता है और एक बड़ा संदेश देता है कि मंत्री या नेता बनने के बाद कोई बड़ा आदमी नहीं बन जाता, बल्कि उसे जनता के जैसा ही बनकर रहना होगा और जनता के बीच जाकर काम करना होगा।

रायपुर में हुई बैठक में किन मंत्रियों को स्मृति ने लगाई फटकार ?

कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में जो बैठक हुई, वह कोई साधारण या औपचारिक बैठक नहीं थी। स्मृति ईरानी ने साफ शब्दों में मंत्रियों और विधायकों को हिदायत दी कि वे सरकारी बंगलों, गाड़ियों और वीआईपी सुख-सुविधाओं के आराम से बाहर निकलें। चेकिंग और अनुशासन का आलम

यह था कि गाड़ियों को बाहरी गेट पर ही रोक दिया गया और मंत्रियों को भी पैदल अंदर जाना पड़ा। कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब को तो एंट्री लिस्ट में नाम न होने के कारण गेट से ही वापस लौटना पड़ा। स्मृति ने कड़े लहजे में कहा कि आज के बाद से और अभी से अगर कोई भी मंत्री या विधायक जनता और कार्यकर्ताओं से दूरी बनाएगा, तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीआईपी ट्रीटमेंट छोड़िए, सीधे ज़मीनी स्तर पर जाइए और जनता के बीच रहकर काम कीजिए क्योंकि जनता का असली मिजाज बड़े नेता नहीं बल्कि बूथ स्तर का कार्यकर्ता ही समझते हैं।

इन मंत्रियों के खिलाफ शिकायतों का अंبار

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साथ कैबिनेट के 9 ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ पूर्व विधायकों, सांसदों और निगम-मंडल के अध्यक्षों ने शिकायतों का पूरा पुलिंदा खोल दिया है। मंत्रियों को लेकर सबसे ज्यादा शिकायतें सांसदों और निगम-मंडल के पदाधिकारियों के साथ हुई बैठकों में सामने आईं। इस कड़े रुख का असर बैठक के बाद साफ़ देखने को मिला जब कई मंत्रियों के चेहरे बुरी तरह उतरे हुए नजर आए। मंत्रियों से नाराजगी के सीधे सवाल पर सीनियर मंत्री रामविचार नेताम ने सिर्फ दो शब्द कहे- 'नो कमेंट्स'। वहीं, मंत्री राजेश अग्रवाल ने डैमेज कंट्रोल करते हुए कहा कि जिसके ऊपर दायित्व होगा, थोड़ी शिकायत तो होगी ही। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि मंत्री लखनलाल देवांगन तो बैठक खत्म होने और अन्य मंत्रियों के निकलने से करीब एक घंटे पहले ही चुपचाप कार्यालय से रवाना हो गए। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि जब स्मृति ईरानी यहाँ रायपुर में सभी मंत्रियों को डांट-फटकार करके गई हैं, एक सख्त टीचर की तरह सबको अनुशासन सिखा कर गई हैं, तो आने वाले दिनों में यहाँ मंत्रियों का कामकाज कैसा रहता है और ज़मीन पर कितना सुधार होता है। इसके साथ ही, जिन लोगों की शिकायतें गई हैं और जिन मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड लेकर वो सीधे दिल्ली पहुँची हैं, तो वहाँ जाने के बाद केंद्रीय नेतृत्व इस पर क्या विचार करता है और क्या फैसला आता है, इस पर इस वक्त छत्तीसगढ़ के हर छोटे-बड़े नेता की निगाहें टिकी हुई हैं।

छत्तीस वर्ष का छत्तीसगढ़: उपलब्धियों की रोशनी, अधूरे सपनों की छाया



• संपादकीय | राज्योत्सव विशेष

1 नवंबर 2000 को जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ अस्तित्व में आया, तब यह केवल एक प्रशासनिक बँटवारा नहीं था। यह उस पुरानी भावना की जीत थी कि "धान का कटोरा" कहलाने वाली यह धरती, जिसके जंगल, खनिज और मेहनतकश लोग दशकों तक देश की प्रगति में योगदान देते रहे, अपने विकास की दिशा स्वयं तय करे। आज जब राज्य अपने 26 वर्ष पूरे कर रहा है, तो यह अवसर उत्सव का तो है ही, उससे कहीं ज़्यादा आत्ममंथन का है। प्रश्न सीधा है: जो वादे राज्य निर्माण के समय किए गए थे, उनमें से कितने पूरे हुए और कितने आज भी फाइलों और भाषणों में अटके हैं?

जो पाया:

सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि छत्तीसगढ़ ने इन ढाई दशकों में बहुत कुछ हासिल किया है। एक नवगठित राज्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने पैरों पर खड़े होना होती है, और छत्तीसगढ़ ने यह कर दिखाया। राज्य का अपना प्रशासनिक ढाँचा खड़ा हुआ, राजधानी के रूप में नया रायपुर आकार लेता गया और जिलों की संख्या बढ़ने के साथ शासन कुछ हद तक लोगों के करीब पहुँचा।

कृषि इस राज्य की आत्मा है, और किसानों के लिए धान खरीदी की संगठित व्यवस्था एक बड़ा सहारा बनी है। सहकारी समितियों के माध्यम से समर्थन मूल्य पर खरीदी, उपार्जन केंद्रों का जाल और किसानों के खातों में सीधा भुगतान, ये सब ऐसी व्यवस्थाएँ हैं जिनसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है। यह अलग बात है कि हर साल खरीदी के मौसम में बारदाना, भंडारण और परिवहन की शिकायतें उठती हैं, लेकिन ढाँचा मौजूद है, यह उपलब्धि है।

ऊर्जा और उद्योग के मोर्चे पर भी राज्य की पहचान मज़बूत हुई है। कोयले और लौह अयस्क से समृद्ध इस भूमि ने देश को बिजली और इस्पात की ताकत दी है। भिलाई इस्पात संयंत्र दशकों से देश के औद्योगिक नक्शे पर राज्य का गौरव रहा है, जबकि कोरबा और रायगढ़ जैसे क्षेत्र बिजली और खनन के बड़े केंद्र बने हैं। बिजली के मामले में राज्य की गिनती सरप्लस राज्यों में होती रही है।

शिक्षा और स्वास्थ्य के उच्च संस्थानों ने भी राज्य की छवि बदली है। एम्स रायपुर, आईआईटी भिलाई, आईआईएम रायपुर, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय और

अनेक मेडिकल कॉलेज इस बात के प्रतीक हैं कि यहाँ के युवाओं को अब हर बार बाहर का रुख नहीं करना पड़ता। सड़कों और रेल संपर्क के विस्तार ने दूरस्थ अंचलों को मुख्यधारा से जोड़ने का काम किया है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को भी इस राज्य की एक उल्लेखनीय सफलता माना जाता रहा है। गरीब परिवारों तक अनाज पहुँचाने की व्यवस्था ने भुखमरी के भय को काफी हद तक कम किया है। इसी तरह छत्तीसगढ़ी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिलना और लोक संस्कृति, तीज-त्योहारों, गोदना, धोकरा शिल्प, कोसा और बस्तर की कला को राज्य स्तर पर मिली पहचान, हमारी सांस्कृतिक अस्मिता के लिए महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। चित्रकोट, सिरपुर और मैनपाट जैसे स्थलों ने पर्यटन की संभावनाओं को नई दिशा दी है।

बस्तर की बात किए बिना यह सूची अधूरी रहेगी। दशकों तक हिंसा की छाया में जी रहे इस अंचल में हाल के वर्षों में नक्सल गतिविधियों में उल्लेखनीय कमी आई है। सुरक्षा बलों की कार्रवाई, आत्मसमर्पण और नए सड़क-संपर्क ने उम्मीद जगाई है। लेकिन शांति की यह उम्मीद तभी स्थायी होगी जब वहाँ के लोगों को विकास में हिस्सेदार बनाया जाए, केवल दर्शक नहीं।

जो अधूरा है: सपनों और सच्चाई के बीच की खाई

अब उस हिस्से पर आते हैं जिस पर उत्सव के शोर में अक्सर बात नहीं होती। कुपोषण और स्वास्थ्य सुविधाएँ आज भी राज्य की सबसे बड़ी कमज़ोरियों में हैं। शहरों में बड़े अस्पताल खुले हैं, लेकिन ग्रामीण और आदिवासी इलाकों के स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों, विशेषज्ञों और दवाओं की कमी की शिकायतें पुरानी हैं। प्रसव के लिए मरीज़ को कई किलोमीटर खाट या एंबुलेंस में ले जाने की तस्वीरें आज भी विचलित करती हैं। जब तक सबसे दूर बैठे नागरिक को भरोसेमंद इलाज नहीं मिलता, तब तक स्वास्थ्य के आँकड़े अधूरे ही रहेंगे।

शिक्षा की स्थिति भी मिली-जुली है। भवन बने हैं, स्कूलों की संख्या बढ़ी है, पर शिक्षकों के रिक्त पद, युक्तिकरण के नाम पर स्कूलों का विलय और सीखने के स्तर की चिंता बनी हुई है। सवाल केवल स्कूल खोलने का नहीं, बच्चे के पढ़ना-लिखना और गणित सीखने का है। उच्च शिक्षा में भी

गुणवत्ता और रोज़गारोन्मुख पाठ्यक्रमों की कमी खलती है।

इसी से जुड़ा है रोज़गार का प्रश्न। राज्य में पर्याप्त संसाधन होने के बावजूद बड़ी संख्या में श्रमिक काम की तलाश में दूसरे राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हैं। यह विडंबना है कि जिस धरती के गर्भ में कोयला और लोहा है, उसके युवा ईट-भट्ठों और निर्माण स्थलों पर दूसरे प्रदेशों में मज़दूरी करते हैं। खनिज आधारित उद्योग कच्चा माल तो ले जाते हैं, पर स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण और रोज़गार के अवसर उस अनुपात में नहीं बन पाए। राज्य को अब केवल खनिज बेचने वाली अर्थव्यवस्था से आगे बढ़कर मूल्य संवर्धन और लघु उद्योगों की ओर देखना होगा।

विकास की कीमत का प्रश्न सबसे गंभीर है। खनन और औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जंगल कटे, गाँव उजड़े और कई परिवार विस्थापन का दर्द झेल रहे हैं। हसदेव अरण्य जैसे क्षेत्रों को लेकर विवाद बताते हैं कि विकास और संरक्षण के बीच संतुलन अब भी साधा जाना बाकी है। पेड़ों की कटाई, जल स्रोतों पर दबाव और उद्योगों से बढ़ता प्रदूषण रायपुर, भिलाई और कोरबा जैसे शहरों की हवा में महसूस होता है। जिन्हें विकास की परियोजनाओं से सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, उन्हें उसका लाभ सबसे कम मिलता है, यह असंतुलन चिंताजनक है।

आदिवासी अधिकारों का प्रश्न भी इसी से जुड़ा है। वन अधिकार कानून और पेसा जैसे प्रावधान कागज़ पर मज़बूत हैं, पर ग्राम सभाओं की वास्तविक भूमिका और सहमति की प्रक्रिया पर अक्सर सवाल उठते हैं। लघु वनोपज, जैसे तेंदूपत्ता, महुआ और लाख, इकट्ठा करने वालों को उचित दाम और समय पर भुगतान मिलना उनकी आजीविका का आधार है। बस्तर में शांति के बाद अब असली परीक्षा यही है कि स्कूल, अस्पताल, बाज़ार और रोज़गार वहाँ तक पहुँचें और स्थानीय समुदाय की बात सुनी जाए।

शहरी विकास के मोर्चे पर नया रायपुर की कहानी हमें सबक देती है। भव्य योजनाएँ बनीं, इमारतें खड़ी हुईं, लेकिन जीवंत शहर बनने की यात्रा अभी बाकी है। वहीं पुराने शहरों में जलनिकासी, यातायात, कचरा प्रबंधन और अतिक्रमण जैसी रोज़मर्रा की समस्याएँ जस की तस हैं। स्थानीय निकायों और पंचायतों में पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों की भागीदारी को मज़बूत किए बिना सुशासन का दावा खोखला रहेगा।

और अंत में भाषा और संस्कृति। छत्तीसगढ़ी को

राजभाषा का दर्जा तो मिला, पर स्कूली शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में उसका स्थान अब भी सीमित है। गोंडी, हल्बी, कुड़ुख और सादरी जैसी बोलियाँ पीढ़ी-दर-पीढ़ी कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। जो समाज अपनी भाषा खोता है, वह अपनी स्मृति और अपने ज्ञान का एक बड़ा हिस्सा भी खो देता है। पहचान की लड़ाई से बना राज्य अपनी भाषाई विविधता की रक्षा में पीछे नहीं रह सकता।

समृद्धि राज्य की राह

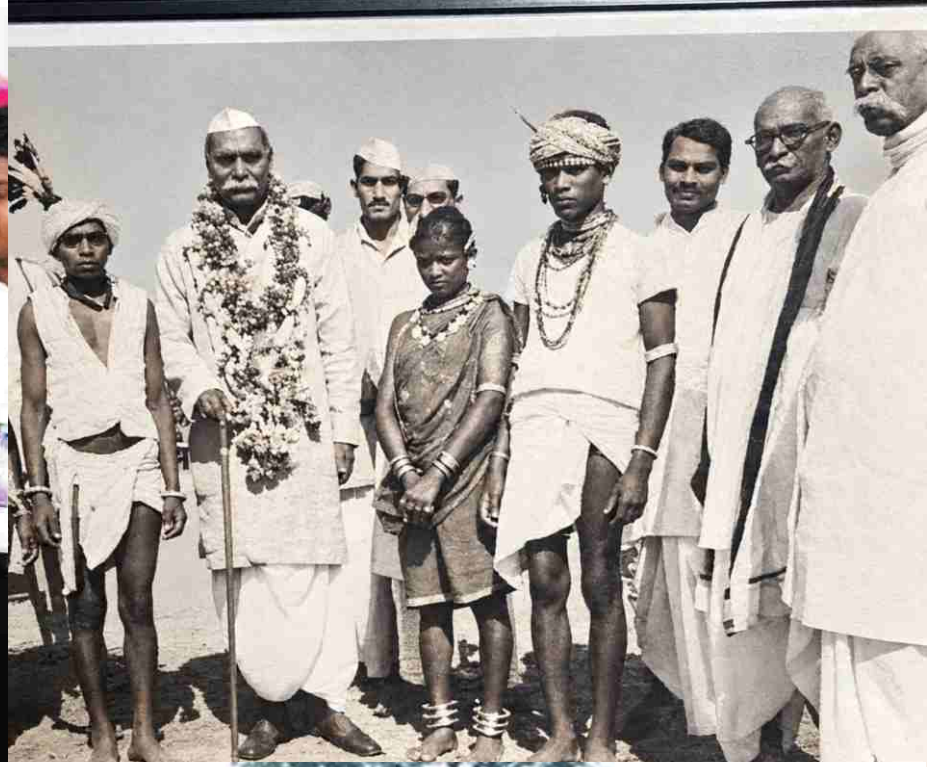
26 वर्ष किसी राज्य के जीवन में किशोरावस्था की दहलीज़ से आगे का पड़ाव है, जहाँ बहाने कम और जवाबदेही ज़्यादा होती है। अब यह तर्क पर्याप्त नहीं कि राज्य अभी नया है। जो काम बाकी हैं, उनके लिए दृढ़ इच्छाशक्ति, स्पष्ट प्राथमिकताएँ और ज़मीनी निगरानी चाहिए। विकास को केवल सड़कों, इमारतों और निवेश के आँकड़ों से नहीं, बल्कि इस पैमाने पर आँका जाना चाहिए कि अंतिम पंक्ति में खड़े किसान, मज़दूर, आदिवासी और महिला के जीवन में कितना बदलाव आया।

राज्य को तीन बातों पर ध्यान देना होगा: पहला, स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में गाँव-गाँव तक गुणवत्ता सुनिश्चित करना। दूसरा, स्थानीय रोज़गार और उद्योग को बढ़ावा देकर पलायन रोकना और संसाधनों का लाभ स्थानीय समुदायों तक पहुँचाना। तीसरा, पर्यावरण और आदिवासी अधिकारों का सम्मान करते हुए ऐसा विकास मॉडल अपनाना जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जंगल, पानी और ज़मीन बचाकर रखे।

राज्योत्सव का असली अर्थ मंचों की रौनक नहीं, बल्कि वह संकल्प है जो हर साल हमें याद दिलाए कि छत्तीसगढ़ महतारी की सेवा का काम अभी पूरा नहीं हुआ। उपलब्धियों पर गर्व करना स्वाभाविक है, पर कमियों से आँख चुराना भविष्य के साथ अन्याय होगा। आइए, इस राज्य स्थापना दिवस पर हम सब, सरकार, समाज और मीडिया, यह संकल्प लें कि अगले पड़ाव तक पहुँचते-पहुँचते छत्तीसगढ़ केवल संसाधनों से ही नहीं, बल्कि समानता, सम्मान और अवसरों से भी समृद्ध राज्य बने।

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ।

बस्तर से रहा राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों का खास लगाव



• प्रितेश बंगारे, संवाददाता, रायपुर

बस्तर। छत्तीसगढ़ का आदिवासी बहुल बस्तर अपनी प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध जनजातीय संस्कृति और ऐतिहासिक परंपराओं के लिए देशभर में पहचान रखता है। आजादी के बाद से ही देश के शीर्ष संवैधानिक और राजनीतिक नेतृत्व का इस क्षेत्र से विशेष जुड़ाव रहा है। अब तक पांच राष्ट्रपति और सात प्रधानमंत्री बस्तर का दौरा कर चुके हैं।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 23 अक्टूबर को बस्तर दशहरा के प्रसिद्ध मुरिया दरबार में शिरकत की। इससे पहले वह इसी साल 7 फरवरी को बस्तर पंडुम में शामिल होने बस्तर आई थीं। उनके दौरने ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर बस्तर की जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को चर्चा में ला दिया है।

1953 में बस्तर पहुंचे थे प्रथम राष्ट्रपति

देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद 23 मार्च 1953 को बस्तर पहुंचे थे। उनके साथ मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल भी मौजूद थे। जगदलपुर से लगभग 18 किलोमीटर दूर ग्रामीणों के आमंत्रण पर वह एक गांव पहुंचे थे।

यहां उन्होंने ग्रामीणों के श्रमदान से निर्मित छात्रावास का उद्घाटन किया था। इसके साथ ही उन्होंने गांव में कुएं के निर्माण के लिए भूमिपूजन भी किया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, उस समय शुरू किया गया कुआं आज भी मौजूद है।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने दौर के दौरान देश के पुनर्निर्माण में जनभागीदारी और श्रमदान की भूमिका पर जोर दिया था। उन्होंने लोगों से सामुदायिक कार्यों में आगे बढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया था।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने शिक्षा का दिया संदेश

भारत के पूर्व राष्ट्रपति और प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का भी बस्तर से गहरा संबंध रहा। रक्षा वैज्ञानिक के रूप में वह कई बार इस क्षेत्र में आए थे। बस्तर के गिरोला और मारडूम में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) के केंद्रों की स्थापना में भी उनकी पहल का योगदान बताया जाता है।

राष्ट्रपति बनने के बाद 4 जून 2004 को डॉ. कलाम ने बस्तर जिले के तोकापाल विकासखंड स्थित रानसरगीपाल गांव का दौरा किया था। यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए बच्चों और युवाओं को जीवन में लक्ष्य निर्धारित करने का संदेश दिया था।

डॉ. कलाम ने शिक्षा को देश के भविष्य की मजबूत नींव बताते हुए हर बच्चे को शिक्षित करने की जरूरत पर बल दिया था। उनका संदेश था कि लक्ष्य तय करके निरंतर प्रयास करने से सफलता की राह बनाई जा सकती है।

प्रतिभा पाटिल ने की थी चित्रकोट की प्रशंसा

बस्तर पहुंचने वाली तीसरी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल थीं। उन्होंने 29 सितंबर 2008 को अपने परिवार के साथ बस्तर का दौरा किया था। इस दौरान वह विश्वप्रसिद्ध चित्रकोट जलप्रपात पहुंचीं और यहां की प्राकृतिक सुंदरता से प्रभावित हुईं।

प्रतिभा पाटिल ने बस्तर में पर्यटन की संभावनाओं को रेखांकित करते हुए पर्यटकों के लिए सुविधाओं के विस्तार की आवश्यकता बताई थी। उन्होंने इस क्षेत्र को देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में स्थान दिलाने की संभावनाओं पर जोर दिया था।

उन्होंने बस्तर की जनजातीय संस्कृति और प्राकृतिक संपदा की सराहना करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश

भी दिया था। उनका दौरा बस्तर की प्राकृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण रहा।

रामनाथ कोविंद ने शिक्षा और स्वास्थ्य पर दिया जोर

बस्तर आने वाले चौथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। उन्होंने 25 और 26 जुलाई 2018 को दो दिवसीय बस्तर प्रवास किया था। इस दौरान उन्होंने दंतेवाड़ा स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर में दर्शन किए और चित्रकोट जलप्रपात का भी दौरा किया।

26 जुलाई को उन्होंने डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलीराम कश्यप स्मृति मेडिकल कॉलेज में संचालित शहीद महेंद्र कर्मा स्मृति चिकित्सालय का लोकार्पण किया था। इस अवसर पर आयोजित सभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया।

रामनाथ कोविंद ने बस्तर के युवाओं को डॉक्टर, इंजीनियर और प्राध्यापक बनने के लिए प्रेरित किया था। उनका संदेश था कि शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं क्षेत्र के विकास तथा लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए अहम हैं।

द्रौपदी मुर्मु ने भी दिया जनजातीय समाज को संदेश

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु बस्तर आने वाली पांचवीं राष्ट्रपति हैं। जनजातीय समाज से आने वाली राष्ट्रपति मुर्मु ने भी शिक्षा को सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए लोगों से इसे अपनाने का आह्वान किया है।

7 फरवरी को बस्तर पंडुम में शामिल होने के बाद 23 अक्टूबर को बस्तर दशहरा के मुरिया दरबार में उनकी उपस्थिति ने क्षेत्र की सांस्कृतिक परंपराओं को राष्ट्रीय महत्व के केंद्र में रखा। मुरिया दरबार बस्तर दशहरा की

प्रमुख परंपराओं में शामिल है, जहां जनजातीय समाज की भागीदारी और परंपराओं का विशेष महत्व है।

सात प्रधानमंत्रियों ने भी किया बस्तर का दौरा

राष्ट्रपतियों के अलावा देश के प्रधानमंत्रियों का भी बस्तर से जुड़ाव रहा है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक कुल सात प्रधानमंत्री बस्तर का दौरा कर चुके हैं।

बस्तर के प्रति राष्ट्रीय नेतृत्व की इस रुचि के पीछे यहां की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक संपदा, ऐतिहासिक परंपराएं और विकास की संभावनाएं महत्वपूर्ण कारण माने जाते हैं। हालांकि, प्रत्येक प्रधानमंत्री के दौर की तारीख, उद्देश्य और उपलब्धियों का विस्तृत विवरण अलग-अलग ऐतिहासिक अभिलेखों से सत्यापित किया जाना आवश्यक है।

परंपरा, विकास और राष्ट्रीय पहचान का संगम है बस्तर

राष्ट्रपतियों के ऐतिहासिक दौरों पर नजर डालें तो बस्तर से जुड़े संदेशों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सामुदायिक भागीदारी, पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय संस्कृति जैसे विषय प्रमुख रहे हैं। अलग-अलग समय पर आए राष्ट्रपतियों ने क्षेत्र की संभावनाओं और चुनौतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

आज बस्तर की पहचान केवल प्राकृतिक सौंदर्य और सांस्कृतिक विरासत तक सीमित नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ने की संभावनाएं भी इसे राष्ट्रीय चर्चा का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु का मुरिया दरबार में शामिल होना इसी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक जुड़ाव की एक नई कड़ी है।

सिर्फ अंकिता शर्मा ही नहीं, कई जिलों में अफसरों ने की हर्ष फायरिंग; एसपी को नोटिस मिलने के बाद छिड़ी बहस

रायपुर। छत्तीसगढ़ में विजयादशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन के बाद पुलिस अधिकारियों द्वारा हर्ष फायरिंग किए जाने का मामला चर्चा में है। 20 अक्टूबर 2026, मंगलवार को दशहरे के अवसर पर राजनांदगांव सहित प्रदेश के कई जिलों से पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा हथियार चलाए जाने के वीडियो सामने आए। हालांकि, राजनांदगांव की एसपी अंकिता शर्मा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला ज्यादा सुर्खियों में आया। पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर रेंज आईजी अजय यादव के माध्यम से अंकिता शर्मा को नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा गया।

इस मामले में फिलहाल अंकिता शर्मा को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि हुई है। दूसरी ओर, अन्य जिलों में भी फायरिंग के वीडियो सामने आने के बाद सवाल उठ रहे हैं कि यदि शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग की प्रथा कई जगह प्रचलित है, तो सुरक्षा नियमों और विभागीय जवाबदेही का निर्धारण किस आधार पर किया जाना चाहिए।

अंकिता शर्मा के वीडियो ने रबीचा ध्यान, आईजी ने मांगा जवाब

राजनांदगांव के रक्षित केंद्र में शस्त्र पूजन के बाद एसपी अंकिता शर्मा द्वारा एके-47 से हवाई फायरिंग किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो में अंकिता शर्मा पारंपरिक भारतीय परिधान साड़ी पहने नजर आईं। उनके इस पहनावे को लेकर भी सोशल मीडिया पर चर्चा हुई, लेकिन विवाद का प्रमुख मुद्दा हथियार चलाने की प्रक्रिया और सुरक्षा व्यवस्था रहा।

वीडियो सामने आने के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने हथियार संभालने के तरीके पर सवाल उठाए। इसके बाद पुलिस मुख्यालय ने मामले का संज्ञान लेते हुए अंकिता शर्मा से जवाब मांगा।

राजनांदगांव रेंज के आईजी अजय यादव ने मीडिया को बताया कि पुलिस मुख्यालय के निर्देश पर नोटिस जारी किया गया है। अंकिता शर्मा का जवाब मिलने के बाद वे अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट वरिष्ठ अधिकारियों को भेजेंगे। आगे की कार्रवाई पुलिस मुख्यालय के स्तर पर तय होगी।

कई जिलों में भी सामने आए फायरिंग के वीडियो

मामले में सामने आई तस्वीरों और मीडिया रिपोर्टों में बिलासपुर के एसएसपी रजनेश सिंह, कवर्धा के एसपी जितेंद्र यादव, बलौदाबाजार के एसपी गौरव रामप्रवेश, मुंगेली के एसपी भोजराम पटेल, कोंडागांव के एसपी

पंकज चंद्रा और सुकमा के एसपी मयंक गुर्जर के नाम शामिल हैं।

इसके अलावा रायपुर पुलिस कमिश्नर डॉ. संजीव शुक्ला, रायगढ़ के एसपी शशिमोहन सिंह और मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी के एसपी यशपाल सिंह का नाम भी इस खबर के संदर्भ में सामने आया है।

पूर्व सैन्य अधिकारी कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने उठाए सवाल

अंकिता शर्मा का वीडियो वायरल होने के बाद पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल कंवलजीत सिंह ढिल्लों ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर आठ बिंदुओं में अपनी आपत्ति रखी। उन्होंने हथियार को संभालने के तरीके, लोडेड हथियार के इस्तेमाल और आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए।

उनकी आपत्ति का मुख्य आधार यह था कि हथियार चलाने समय निर्धारित सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन जरूरी है। भीड़ या अन्य लोगों की मौजूदगी में हथियार संभालने में लापरवाही गंभीर जोखिम पैदा कर सकती है। उन्होंने मामले में सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की।

विजयादशमी में हर्ष फायरिंग का वैधानिक अधिकार नहीं

छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजीपी डीएम अवस्थी ने शस्त्र पूजन के दौरान हवाई फायरिंग किए जाने की परंपरा पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि पुलिस रेगुलेशन या पुलिस एक्ट में शस्त्र पूजन के अवसर पर हवाई फायरिंग करने का कोई स्पष्ट कानूनी या वैधानिक अधिकार दर्ज नहीं है।

अवस्थी के अनुसार, पुलिसकर्मी निर्धारित फायरिंग रेंज में अभ्यास के दौरान या कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक परिस्थितियों में हथियारों का इस्तेमाल करते हैं। फायरिंग रेंज में भी निर्धारित मैनुअल का पालन करना अनिवार्य है।

उन्होंने यह भी कहा कि 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे अवसरों पर होने वाली औपचारिक फायरिंग में ब्लैंक यानी आवाजी कारतूस का इस्तेमाल किया जाता है। कारतूसों का हिसाब रखना भी जरूरी है। उनके मुताबिक, शस्त्र पूजन के दौरान हथियारों की पूजा करने और हथियार चलाने को एक ही बात नहीं माना जाना चाहिए।

अवस्थी ने वायरल वीडियो में हथियार पकड़ने और संभालने के तरीके पर भी आपत्ति जताई। उनके बयान के अनुसार, शस्त्र पूजन के बाद हवाई फायरिंग को किसी परंपरा का हिस्सा बताना अपने आप में उसे वैधानिक अधिकार नहीं बना देता।

साड़ी पहनने पर भी सोशल मीडिया में चर्चा

अंकिता शर्मा के वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर उनके पहनावे को लेकर भी अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आईं।

उन्होंने शस्त्र पूजन के दौरान साड़ी पहनी थी, जो पारंपरिक भारतीय परिधान है। उनके समर्थक इसे भारतीय संस्कृति और परंपरा से जुड़ा विषय बताते हुए उनके पहनावे को लेकर होने वाली आलोचना पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरी ओर, आलोचकों का कहना है कि किसी अधिकारी के पहनावे से अलग, हथियार चलाने के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए साड़ी पहनने और हथियार चलाने की सुरक्षा को अलग-अलग मुद्दों के रूप में देखना जरूरी है। पहनावे के आधार पर किसी



अधिकारी के प्रशिक्षण या क्षमता के बारे में निष्कर्ष निकालने के बजाय वास्तविक प्रक्रिया, सुरक्षा इंतजामों और लागू नियमों पर चर्चा होनी चाहिए।

सोशल मीडिया पर दो पक्षों में बंटी राय

इस पूरे मामले में अब लोगों की राय दो हिस्सों में बंटी दिखाई दे रही है। एक पक्ष अंकिता शर्मा के समर्थन में है और उनका कहना है कि शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग की प्रथा कई जिलों में प्रचलित रही है। ऐसे में केवल एक अधिकारी को निशाने पर रखकर चर्चा करना उचित नहीं है।

दूसरा पक्ष हथियारों के इस्तेमाल के दौरान सुरक्षा, अनुशासन और जवाबदेही को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। उनका सवाल है कि यदि दूसरे जिलों में भी इसी तरह की गतिविधियां हुई हैं, तो वहां की परिस्थितियों और सुरक्षा प्रक्रियाओं की भी जांच होनी चाहिए।

हालांकि, सोशल मीडिया पर किसी अधिकारी के समर्थन या विरोध में राय बनना और विभागीय जांच में नियमों का उल्लंघन साबित होना दो अलग-अलग बातें हैं।

अब पुलिस मुख्यालय के फैसले पर नजर

फिलहाल अंकिता शर्मा को नोटिस जारी किए जाने की पुष्टि हुई है। उनका जवाब मिलने के बाद आईजी अजय यादव अपनी टिप्पणी के साथ रिपोर्ट पुलिस मुख्यालय भेजेंगे। इसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा।

साथ ही, दूसरे जिलों से सामने आए वीडियो के संबंध में पुलिस विभाग क्या रुख अपनाता है, यह भी महत्वपूर्ण होगा। यदि शस्त्र पूजन के बाद फायरिंग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देशों की आवश्यकता है, तो पूरे प्रदेश में एक समान नियम और सुरक्षा प्रक्रिया तय करने की मांग भी इस विवाद से उठ रही है।



रायपुर में भगवान भरोसे चल रहा स्कूल: एक हफ्ते से नहीं आए शिक्षक, SIR ड्यूटी के चलते 166 बच्चों का भविष्य दांव पर



• राकेश निर्मलकर, संवाददाता, रायपुर

रायपुर। रायपुर जिले के धरसीवा विकासखंड अंतर्गत शासकीय माध्यमिक शाला पिरदा से शिक्षा व्यवस्था की बदहाली को उजागर करने वाली एक बड़ी खबर सामने आई है। इस मिडिल स्कूल में छठवीं से आठवीं कक्षा तक कुल 166 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से स्कूल में एक भी शिक्षक पढ़ाने नहीं आया है। जानकारी के मुताबिक, स्कूल के सभी शिक्षकों को 'SIR' (स्पेशल समरी रिवीजन) कार्य के तहत BLO (बूथ लेवल ऑफिसर) की ड्यूटी में लगा दिया गया है। शिक्षकों के

नदारद रहने से बच्चों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप पड़ गई है और उनका भविष्य राम भरोसे है।

ग्रामीणों ने जताई कड़ी नाराजगी और सुरक्षा की चिंता

स्कूल की इस स्थिति पर ग्रामीणों ने गहरी चिंता व्यक्त की है। ग्रामीणों का कहना है कि शिक्षकों के नहीं होने से बच्चों का भविष्य अंधकार में जा रहा है। उन्होंने प्रशासन की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब अन्य कार्यों के लिए सरकार टेंडर निकाल सकती है, तो BLO जैसे काम के लिए बेरोजगार युवाओं को 10-12 हजार रुपये देकर एक महीने के लिए नियुक्ति क्यों नहीं दी जा सकती?

ग्रामीणों ने एक बड़ी और गंभीर चिंता यह भी जताई कि स्कूल का गेट खुला रहता है; ऐसे में अगर कोई असामाजिक तत्व (उपद्रवी) स्कूल में घुस जाए या अचानक किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, चक्कर आ जाए, तो वहां उनकी देखरेख करने या जिम्मेदारी लेने वाला कोई मौजूद नहीं है।

प्राइमरी स्कूल के प्रभारी शिक्षक की मजबूरी

इसी स्कूल परिसर में एक प्राइमरी स्कूल भी संचालित होता है, जिसमें 167 बच्चे दर्ज हैं। इस प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने बताया कि उनके स्कूल में कुल 7 शिक्षकों का स्टाफ है, जिनमें से 4 शिक्षकों की ड्यूटी भी SIR (BLO) में लगा दी गई है। मिडिल स्कूल के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें केवल मौखिक रूप से मिडिल स्कूल की 'देखरेख' करने को कहा गया है। जबकि मिडिल स्कूल में पढ़ाई-लिखाई बिल्कुल नहीं हो रही है।

बच्चे खुद लगा रहे हाजिरी, सिलेबस अधूरा

शिक्षकों के न आने पर बच्चों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए कहा कि वे क्लास में खुद ही एक-दूसरे की हाजिरी ले रहे हैं। बच्चे स्कूल आकर खुद से किताबें खोलकर पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं और अपनी कॉपियां पूरी कर रहे हैं। बच्चों ने बताया कि उनकी अर्द्धवार्षिक परीक्षाएं नजदीक हैं, लेकिन अब तक मात्र दो से छह पाठ ही पढ़ाए गए हैं। शिक्षक न होने के कारण

उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वे आगे की पढ़ाई कैसे करें।

जिम्मेदार अधिकारियों ने साधी चुप्पी

इस बेहद गंभीर मामले पर जब शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों से उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, तो उनका रवैया भी निराशाजनक रहा। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी (BEO) ने फोन का कोई जवाब नहीं दिया (फोन नहीं उठाया)। वहीं, जब जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो वे अपने कार्यालय में नहीं मिले और उनका फोन भी नहीं लगा।

'ठीहा छत्तीसगढ़' की विस्तृत रिपोर्ट

आपको बता दें कि शिक्षा व्यवस्था की इस बदहाली और बच्चों की परेशानी को लेकर प्रदेश के प्रमुख डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म 'ठीहा छत्तीसगढ़' ने 27 अक्टूबर को ग्रांड उज्ज्वी से इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की थी, जिसमें इस पूरे मामले को प्रमुखता से सामने लाया गया है।

छत्तीसगढ़ के तोमन ने जीता एशियन पैरा गेम्स में स्वर्ण

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व कमांडो तोमन कुमार ने एशियन पैरा गेम्स 2026 में स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। जापान के आइची-नागोया में 22 अक्टूबर को तोमन कुमार और भारतीय तीरंदाज शीतल देवी की जोड़ी ने कंपाउंड मिश्रित टीम स्पर्धा के फाइनल में इंडोनेशिया को 151-148 से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की।

यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान अपना बायां पैर गंवाने वाले तोमन ने कठिन परिस्थितियों से उबरकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है। उनकी इस सफलता को संघर्ष, साहस और दृढ़ इच्छाशक्ति की मिसाल के रूप में देखा जा रहा है।

पैरा तीरंदाजी में भारत को पहला स्वर्ण

शीतल देवी और तोमन कुमार की जोड़ी ने फाइनल में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को एशियन पैरा गेम्स की पैरा तीरंदाजी स्पर्धा में पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दोनों खिलाड़ियों ने पूरे मुकाबले में संयम बनाए रखा और दबाव के बीच सटीक निशाने लगाकर इंडोनेशिया को पीछे छोड़ दिया।

इस जीत के साथ भारत के खाते में प्रतियोगिता का 16वां स्वर्ण पदक जुड़ गया। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस सफलता के बाद भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया। भारतीय जोड़ी की जीत ने देश के पैरा खेलों में बढ़ते प्रदर्शन को भी रेखांकित किया।

क्वालिफाइंग राउंड में बनाया विश्व रिकॉर्ड

फाइनल से पहले शीतल देवी और तोमन कुमार ने क्वालिफाइंग राउंड में भी असाधारण प्रदर्शन किया था। भारतीय जोड़ी ने कुल 1402 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड कायम किया और शीर्ष स्थान प्राप्त किया। इसके बाद फाइनल में भी दोनों ने अपने प्रदर्शन का स्तर बनाए रखा।

मुकाबले के पहले सेट में भारत ने 38-37 से बढ़त बनाई। दूसरे सेट के बाद भारतीय जोड़ी का स्कोर 77-73 हो गया। तीसरे सेट में इंडोनेशिया ने एक अंक की बढ़त हासिल की, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने मुकाबले पर अपनी पकड़ बनाए रखी।

आखिरी सेट में दोनों टीमों ने 38-38 अंक हासिल

किए। इसके बावजूद शुरुआती सेटों में बनाई गई बढ़त भारत के लिए निर्णायक साबित हुई। भारतीय जोड़ी ने कुल 151-148 के स्कोर से मुकाबला जीतकर स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

शीतल देवी ने हौसले से बनाई अलग पहचान

भारतीय तीरंदाज शीतल देवी की कहानी भी प्रेरणादायक है। जन्म से दोनों हाथ नहीं होने के बावजूद उन्होंने तीरंदाजी में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बनाई है। वह धनुष को संभालने के लिए पैरों का इस्तेमाल करती हैं और कंधे तथा जबड़े की मदद से धनुष की डोरी खींचकर निशाने लगाती हैं।

वर्ष 2019 में भारतीय सेना ने उनकी प्रतिभा को पहचाना। इसके बाद उन्होंने कटरा में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मार्गदर्शन में

प्रशिक्षण प्राप्त किया। लगातार मेहनत और अभ्यास के दम पर उन्होंने पैरा तीरंदाजी में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कीं। वर्ष 2023 में शीतल देवी विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ऐसी महिला तीरंदाज बनीं, जिनके दोनों हाथ नहीं हैं। वह विश्व चैंपियनशिप और

पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी पदक जीत चुकी हैं। विश्व तीरंदाजी संस्था उन्हें दो बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुन चुकी है। नक्सल विरोधी अभियान में गंवाया पैर, नहीं हारी हिम्मत तोमन कुमार की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। फरवरी 2022 में झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सेवा देते समय वह आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा। गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ा। वर्ष 2023 में कृत्रिम पैर से संबंधित

सलाह लेने के दौरान उनका परिचय पैरा तीरंदाजी से हुआ। इसके बाद उन्होंने इस खेल में प्रशिक्षण शुरू किया और

पेरिस पैरालंपिक 2024 में भी पदक जीत चुकी हैं। विश्व तीरंदाजी संस्था उन्हें दो बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ पैरा तीरंदाज चुन चुकी है।

नक्सल विरोधी अभियान में गंवाया पैर, नहीं हारी हिम्मत

तोमन कुमार की सफलता के पीछे संघर्ष की लंबी कहानी है। फरवरी 2022 में झारखंड में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में सेवा देते समय वह आईईडी विस्फोट की चपेट में आ गए थे। इस हादसे में उन्हें अपना बायां पैर गंवाना पड़ा।

गंभीर चोट के बावजूद उन्होंने जीवन में आगे बढ़ने का हौसला नहीं छोड़ा। वर्ष 2023 में कृत्रिम पैर से संबंधित



धीरे-धीरे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा साबित की।

विश्व चैंपियन बनने के बाद एक और ऐतिहासिक उपलब्धि

तोमन कुमार ने वर्ष 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में आयोजित विश्व चैंपियनशिप के कंपाउंड पुरुष ओपन वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था। इस उपलब्धि के साथ वह पैरा तीरंदाजी में विश्व चैंपियन बनने वाले भारत के पहले पुरुष तीरंदाज बने।

अब एशियन पैरा गेम्स 2026 में शीतल देवी के साथ स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया है। उनकी यह सफलता बताती है कि शारीरिक चुनौतियां किसी व्यक्ति के सपनों और लक्ष्य को हासिल करने की राह में अंतिम बाधा नहीं होतीं।

छत्तीसगढ़ के लिए गौरव का क्षण

तोमन कुमार की इस उपलब्धि ने छत्तीसगढ़ को अंतरराष्ट्रीय खेल मंच पर नई पहचान दिलाई है। देश की सेवा के दौरान गंभीर चोट का सामना करने के बाद खेलों में विश्वस्तरीय सफलता हासिल करना उनकी मेहनत और दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। शीतल देवी और तोमन कुमार की ऐतिहासिक जोड़ी ने यह साबित किया कि हौसला मजबूत हो, तो मुश्किल परिस्थितियों में भी सफलता का नया इतिहास रचा जा सकता है।

महतारी वंदन योजना से माधुरी के हुनर को मिला संबल, दीपावली के लिए गढ़ रही मिट्टी के दीये



बलौदाबाजार। त्योहारों की खुशियां तब और बढ़ जाती हैं, जब मेहनत के साथ आत्मनिर्भरता का भरोसा भी जुड़ जाता है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार नगर के वार्ड क्रमांक 18 में रहने वाली श्रीमती माधुरी पांडे की कहानी इसी बदलाव की एक प्रेरक मिसाल है। दीपावली के अवसर पर वह अपने हाथों से मिट्टी के दीये तैयार करने में जुटी हैं। उनके लिए यह केवल त्योहार की तैयारी नहीं, बल्कि अपनी पारंपरिक कला को आगे बढ़ाने, परिवार की आजीविका में सहयोग करने और आत्मविश्वास के साथ जीवन जीने का अवसर भी है। महतारी वंदन योजना के तहत मिलने वाली

नियमित आर्थिक सहायता ने उनकी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करने में सहारा दिया है।

पारंपरिक हुनर से परिवार की आजीविका में योगदान

श्रीमती माधुरी पांडे अपने पति श्री हरिकिशन पांडे के साथ लंबे समय से कुम्हारी के काम में सहयोग कर रही हैं। विवाह के बाद से ही वह मिट्टी से पारंपरिक और उपयोगी वस्तुएं बनाने के पारिवारिक काम में हाथ बंटाती आ रही हैं। मिट्टी को आकार देकर दीये और अन्य वस्तुएं तैयार करना उनके परिवार के पारंपरिक हुनर का हिस्सा है। यह कला न केवल छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत से जुड़ी है, बल्कि अनेक परिवारों की आजीविका का आधार भी है।

हालांकि, सीमित आर्थिक संसाधनों के बीच अपनी छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा करना उनके लिए हमेशा आसान नहीं था। पहले व्यक्तिगत आवश्यकताओं के लिए उन्हें अपने पति पर निर्भर रहना पड़ता था। वह अपनी जरूरतों को स्वयं पूरा करना चाहती थीं, लेकिन आर्थिक सीमाओं के कारण उनके पास विकल्प कम थे। ऐसे में नियमित आर्थिक सहायता उनके लिए महत्वपूर्ण साबित हुई।

महतारी वंदन योजना से मिली आर्थिक मजबूती

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा संचालित महतारी वंदन योजना के तहत श्रीमती माधुरी पांडे को हर महीने एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिल रही है। इस राशि से वह अपनी रोजमर्रा की छोटी-छोटी जरूरतों को पूरा कर पा रही हैं। साथ ही, त्योहारों के दौरान आवश्यक खर्चों को संभालने में भी उन्हें मदद मिल रही है।

माधुरी के लिए यह सहायता केवल एक हजार रुपये की राशि तक सीमित नहीं है। इससे उन्हें अपनी जरूरतों के संबंध में स्वयं निर्णय लेने और आर्थिक रूप से अधिक सहज महसूस करने का अवसर मिला है। नियमित सहायता से

उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वह पहले की तुलना में अधिक संतोष के साथ अपने पारिवारिक जीवन तथा त्योहारों की तैयारियों में भाग ले पा रही हैं।

दीपावली के लिए मिट्टी के दीये तैयार करने में जुटी माधुरी

दीपावली नजदीक आते ही माधुरी पांडे अपने पारंपरिक हुनर को नया आकार देने में जुट गई हैं। वह मिट्टी से दीये बना रही हैं, जो दीपावली पर घरों को रोशन करने के साथ भारतीय संस्कृति और परंपरा का प्रतीक भी हैं। मिट्टी को गढ़कर दीये तैयार करने की उनकी मेहनत में वर्षों का अनुभव और अपनी कला के प्रति लगाव झलकता है।

उनका हुनर केवल दीपावली तक सीमित नहीं है। इससे पहले वह छत्तीसगढ़ के पारंपरिक पोरा पर्व के लिए मिट्टी के जाता और बैल भी बना चुकी हैं। पोरा पर्व में मिट्टी से बनी पारंपरिक वस्तुओं का विशेष महत्व है। इन वस्तुओं को तैयार करके माधुरी अपने परिवार के पुराने हुनर को जीवित रखने के साथ प्रदेश की लोक संस्कृति को सहेजने में भी योगदान दे रही हैं।

दीपावली के लिए दीये बनाते समय उनके सामने त्योहार की खुशियां और अपनी मेहनत के प्रति संतोष दोनों हैं। उनके हाथों से तैयार होने वाले ये दीये इस बात का प्रतीक हैं कि पारंपरिक कौशल और मेहनत के सहारे परिवार की आजीविका में योगदान दिया जा सकता है। वहीं, नियमित आर्थिक सहायता मिलने से उनकी रोजमर्रा की जरूरतों और त्योहारों की तैयारियों को संभालना पहले से आसान हुआ है।

आर्थिक सहायता से त्योहारों में बढ़ी खुशियां

श्रीमती माधुरी पांडे के अनुसार, महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने मिलने वाली सहायता से अब वह अपनी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर पाती हैं। पहले जिन छोटी-छोटी जरूरतों के लिए उन्हें दूसरों पर निर्भर रहना

पड़ता था, अब उनके लिए उन्हें कुछ आर्थिक सहारा मिल रहा है। इससे तीज-त्योहार मनाने में भी उन्हें अधिक खुशी और संतोष महसूस होता है।

उनका अनुभव बताता है कि नियमित आर्थिक सहायता महिलाओं को अपनी जरूरतों के लिए निर्णय लेने में मदद कर सकती है। हालांकि यह राशि उनकी सभी आर्थिक चुनौतियों का समाधान नहीं है, लेकिन सीमित संसाधनों के बीच छोटी जरूरतों को पूरा करने और आत्मविश्वास बढ़ाने में इसका महत्व है।

“अब अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हूं”

महतारी वंदन योजना से मिले लाभ के बारे में अपनी खुशी जाहिर करते हुए श्रीमती माधुरी पांडे कहती हैं, “पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी पति पर निर्भर रहना पड़ता था। जब से महतारी वंदन योजना के तहत हर महीने एक हजार रुपये मिलने लगे हैं, तब से मैं अपनी जरूरतें खुद पूरी कर पा रही हूं। अब तीज-त्योहार भी खुशी से मना पाते हैं। दीपावली के लिए दीये बना रही हूं। इसके लिए विष्णु भैया का बहुत-बहुत धन्यवाद।”

माधुरी पांडे की कहानी मेहनत, पारंपरिक हुनर और आर्थिक सहयोग के मेल से आगे बढ़ती एक प्रेरक कहानी है। मिट्टी के दीये तैयार करने में जुटी माधुरी अपने हाथों से दीपावली के लिए रोशनी गढ़ रही हैं। उनके लिए इन दीयों में केवल त्योहार की चमक नहीं, बल्कि अपने हुनर को जीवित रखने, परिवार की जिम्मेदारियों में योगदान देने और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने का विश्वास भी शामिल है।

सक्सेस स्टोरी का संदेश: जब महिलाओं के पारंपरिक कौशल को प्रोत्साहन और उनकी जरूरतों के अनुरूप आर्थिक संबल मिलता है, तो उन्हें अपने फैसले स्वयं लेने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। माधुरी पांडे की कहानी इसी बदलाव को उजागर करती है, जहां मिट्टी के दीयों के साथ मेहनत, परंपरा और आत्मनिर्भरता की रोशनी भी जगमगा रही है।

छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बड़ी बैठक

किसान, उपभोक्ता और उद्योग-सबको मिली राहत



रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में आयोजित मंत्रिपरिषद् की बैठक में प्रदेश के किसानों, घरेलू बिजली उपभोक्ताओं, शासकीय कर्मचारियों, खिलाड़ियों, उद्योगों और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने, 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदने, बिजली बिल में राहत जारी रखने और नगर पंचायत कूरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने सहित कई प्रस्तावों को मंजूरी दी।

बैठक में सड़क और रेल अधोसंरचना के विकास, पर्यटन को बढ़ावा देने, शासकीय कर्मचारियों के लिए कैंशलेस चिकित्सा सुविधा, खेल प्रतिभाओं को तैयार करने और औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने से जुड़े फैसले भी लिए गए।

1. 15 नवंबर से धान खरीदी: कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में किसानों से 15 नवंबर से धान खरीदी करने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 27.50 लाख से अधिक किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से अधिकतम 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदा जाएगा।

किसानों को राहत देते हुए एग्रीस्टेक आईडी वाले पिछले वर्ष के पंजीकृत किसानों को धान विक्रय के लिए मान्य किया गया है। ऐसे किसानों को अलग से पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। एग्रीस्टेक में पंजीयन होने के कारण धान बेचने के लिए समिति में ऋण पुस्तिका लाने की अनिवार्यता भी नहीं रहेगी।

डिजिटल क्रॉप सर्वे के माध्यम से धान के रकबे का ऑनलाइन निर्धारण किया जाएगा। वास्तविक किसानों से खरीदी सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था लागू रहेगी। किसानों की सुविधा के लिए 360 नए उपाजर्जन केंद्र शुरू किए जाएंगे। इस तरह प्रदेश में कुल 3100 केंद्रों के माध्यम से धान खरीदी की जाएगी।

इसके अलावा, कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 और 2025-26 के अतिशेष धान का नीलामी के

माध्यम से निराकरण करने के संबंध में मंत्रिमंडलीय उपसमिति के निर्णय का अनुसमर्थन किया।

2. बिजली बिल में राहत मार्च 2027 तक: एम-ऊर्जा योजना के तहत 200 यूनिट तक बिजली बिल में रियायत जारी रहेगी। 400 यूनिट तक मासिक खपत की पात्रता 31 मार्च 2027 तक बढ़ाई गई है। इससे लगभग 7.25 लाख उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा।

3. सड़क निर्माण के लिए राहत: डामर की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए सड़क ठेकेदारों को राहत दी जाएगी। ग्रामीण सड़क कार्यों के लिए 130.88 करोड़ रुपये और अन्य पात्र कार्यों के लिए 70 से 100 करोड़ रुपये तक अतिरिक्त खर्च का अनुमान है।

4. कर्मचारियों को कैंशलेस इलाज: शासकीय कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवारों को सूचीबद्ध अस्पतालों में कैंशलेस चिकित्सा सुविधा मिलेगी। ऑनलाइन प्रक्रिया से इलाज और दावों का निपटारा आसान होगा।

5. मुख्यमंत्री अधोसंरचना मिशन: वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक पांच वर्षों में 500 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है। सड़क निर्माण, गुणवत्ता जांच, डिजिटल निगरानी और सड़क सुरक्षा पर जोर रहेगा।

6. पर्यटन विकास मिशन: अगले पांच वर्षों के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। पर्यटन स्थलों पर सुविधाएं बढ़ाने के साथ होमस्टे, निजी निवेश और रोजगार को बढ़ावा दिया जाएगा।

7. राजनीतिक आंदोलनों के 9 मामले: विशुद्ध राजनीतिक आंदोलनों से जुड़े नौ प्रकरणों को न्यायालय से वापस लेने के लिए आगे की कार्रवाई की अनुमति दी गई।

8. कूरा का नाम होगा कुंवरगढ़: रायपुर जिले की नगर

पंचायत कूरा का नाम बदलकर कुंवरगढ़ करने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।

कुंवरगढ़ को छत्तीसगढ़ के 36 गढ़ों में शामिल ऐतिहासिक स्थल के रूप में बताया गया है। यह क्षेत्र अपने प्राचीन मंदिरों, ऐतिहासिक धरोहरों और तालाबों के लिए जाना जाता है। समय के साथ इसका नाम कूरा प्रचलित हो गया था।

स्थानीय नागरिक लंबे समय से नगर पंचायत को उसकी ऐतिहासिक पहचान कुंवरगढ़ के नाम से पुनः पहचान दिलाने की मांग कर रहे थे। कैबिनेट के फैसले से इस मांग को स्वीकृति मिल गई है।

9. कोल गैसीफिकेशन को प्रोत्साहन: औद्योगिक विकास नीति में संशोधन कर 1000 करोड़ रुपये या उससे अधिक निवेश वाली कोल गैसीफिकेशन परियोजनाओं के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज का प्रावधान किया गया।

10. 295 किलोमीटर की रेल परियोजना: कटघोरा-तखतपुर-मुंगेली-कवर्धा-खैरागढ़-डोंगरगढ़ रेल लाइन को गति देने के लिए 8000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली परियोजना में राज्य और रेल मंत्रालय की हिस्सेदारी को मंजूरी दी गई।

11. पांच सरकारी परिसंपत्तियों का पुनर्विकास: दुर्ग, रामानुजगंज, जशपुर, सक्ती और धमतरी की सरकारी जमीनों एवं परिसंपत्तियों का निजी भागीदारी से पुनर्विकास किया जाएगा। इससे राजस्व और रोजगार बढ़ाने का लक्ष्य है।

12. राजनांदागांव में 10 एकड़ जमीन: ग्राम खपरीकला में केंद्रीय भंडारण निगम को 10 एकड़ भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। इससे भंडारण सुविधाओं का विस्तार होगा।

13. सोमनी में 400 करोड़ का निवेश: राजनांदागांव के सोमनी में मल्टी फ्रूट प्रोसेसिंग फैसिलिटी स्थापित होगी। इससे 1000 से अधिक प्रत्यक्ष और 5000 से अधिक

अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर पैदा होने की संभावना है।

14. सुशासन विभाग में तीन नए पद: सुशासन एवं अभिसरण विभाग में आयुक्त/संचालक, अपर संचालक और विशेषज्ञ स्तर के एक-एक पद के सृजन को मंजूरी दी गई।

15. वन मुख्यालय में नया पद: नवा रायपुर के अरण्य भवन में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक अस्थायी पद एक वर्ष के लिए बनाया जाएगा। इससे विभिन्न सरकारी पोर्टलों से जुड़े कार्यों में तेजी आएगी।

16. परिवार पेंशन को मंजूरी: दिवंगत चिकित्सा प्राध्यापक डॉ. राकेश मोहन चंदोला की सेवा को परिवार पेंशन के लिए नियमित सेवा मानते हुए पात्र परिजनों को पेंशन, बकाया राशि और नियमानुसार ब्याज देने की मंजूरी दी गई।

17. खेल उत्कर्ष मिशन के लिए 100 करोड़: खिलाड़ियों की प्रतिभा पहचानने और उन्हें राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर के लिए तैयार करने हेतु 2026-27 में 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया। पहले चरण में छह शहरों में फीडर सेंटर खुलेंगे।

18. औद्योगिक भूमि नियमों में बदलाव: औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम, 2015 में संशोधन को मंजूरी दी गई। इससे भूमि आवंटन सरल होगा, ई-नीलामी को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक निवेश के लिए सुविधाएं बढ़ेंगी।

19. कृषक उन्नति योजना में संशोधन: धान की खरीदी 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से होगी। योजना के तहत आदान सहायता अब प्रति क्विंटल के बजाय प्रति एकड़ के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे फसल विविधीकरण और आधुनिक कृषि को प्रोत्साहन देने का लक्ष्य है।

मखाना की खेती से आत्मनिर्भर बन रही ग्रामीण महिलाएं

29 एकड़ में मखाना उत्पादन का संग्रहण शुरू, महिला स्व-सहायता समूहों को स्वरोजगार और अतिरिक्त आमदनी की उम्मीद



धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में ग्रामीण महिलाओं की मेहनत अब तालाबों में समृद्धि की नई कहानी लिख रही है। पारंपरिक खेती और घरेलू कामकाज के साथ जीवन बिताने वाली महिलाएं अब मखाना उत्पादन, संग्रहण और प्रसंस्करण के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। जिले के ग्राम छाती और डांडेसरा में महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 29 एकड़ में उत्पादित मखाना का संग्रहण शुरू हो गया है। यह पहल ग्रामीण महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता, स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तिकरण की नई संभावनाएं लेकर आई है।

तालाबों में तैयार हो रही महिलाओं की तरक्की की फसल

धमतरी जिले में मखाना की खेती ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने के साथ कृषि के नए विकल्प के रूप में उभर रही है। ग्राम छाती और डांडेसरा की शैलपुत्री एवं नई किरण महिला स्व-सहायता समूह की सदस्य इस पहल से जुड़कर अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा

रही हैं। तालाबों में तैयार हुई फसल का संग्रहण शुरू होने से समूह की महिलाओं में उत्साह है। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले समय में मखाना उत्पादन के साथ इसकी सफाई, प्रसंस्करण और बाजार में बिक्री से आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे।

महिलाओं के लिए इस पहल का महत्व केवल एक नई फसल उगाने तक सीमित नहीं है। यह उन्हें कृषि आधारित गतिविधियों में भागीदारी बढ़ाने, सामूहिक रूप से काम करने और स्वरोजगार के अवसर तलाशने का मौका भी दे रही है। यदि उत्पादन के साथ तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, तो मखाना की खेती ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

165 एकड़ का लक्ष्य, 105 एकड़ में शुरू हुई खेती

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में प्रदेश में कृषि विविधीकरण और ग्रामीण आजीविका को प्रोत्साहित करने के प्रयासों के बीच धमतरी जिले में मखाना उत्पादन को विस्तार दिया जा रहा है। केंद्र सरकार की 'सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ मखाना' के अंतर्गत वर्ष 2025-26 में जिले को 165 एकड़ में मखाना उत्पादन का लक्ष्य दिया गया था। इसके विरुद्ध जिला प्रशासन और उद्यानिकी विभाग के मार्गदर्शन में 105 एकड़ क्षेत्र में खेती शुरू की गई है।

जिले के ग्राम राखी, छाती, डांडेसरा, पीपरछेड़ी और नगरी विकासखंड के सांकरा में मखाना उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस पहल के माध्यम से तालाबों जैसे उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर खेती के नए विकल्प विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इससे किसानों और महिला स्व-सहायता समूहों को पारंपरिक कृषि गतिविधियों के अतिरिक्त आय के नए अवसर मिल सकते हैं।

वैज्ञानिक प्रशिक्षण से सीखेंगी मखाना प्रसंस्करण की तकनीक

मखाना उत्पादन में अच्छी उपज के साथ बीजों का सही

तरीके से संग्रहण और प्रसंस्करण भी बेहद महत्वपूर्ण है। इसी उद्देश्य से 26 अक्टूबर 2026 को मखाना संग्रहण की शुरुआत के साथ प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिला समूहों को उत्पादन के बाद की प्रक्रियाओं की जानकारी देकर उनकी तकनीकी दक्षता बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है।

मखाना के बीजों का संग्रहण तीन चरणों में किया जाता है। पहले चरण को 'लहसर' कहा जाता है, जिसमें लगभग 70 प्रतिशत बीज निकाले जाते हैं। इसके बाद 'मरकट' और 'कर्कट' चरणों में शेष बीजों का संग्रहण किया जाता है। एकत्रित बीजों की सफाई और धूप में सुखाने के बाद निर्धारित तकनीक के अनुसार भुनाई की जाती है। इसके बाद बीजों को फोड़कर सफेद और कुरकुरा मखाना तैयार किया जाता है, जिसे 'लावा' कहा जाता है।

इस पूरी प्रक्रिया में सावधानी और तकनीकी जानकारी की अहम भूमिका होती है। सही प्रसंस्करण से उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने और बाजार में बेहतर कीमत मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसलिए महिलाओं को केवल उत्पादन तक सीमित न रखकर कटाई-पश्चात प्रबंधन की जानकारी देना भी इस पहल का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

कृषि विज्ञान केंद्र में मिलेगा विशेष प्रशिक्षण

उप संचालक उद्यानिकी के अनुसार, महिला स्व-सहायता समूहों को आगामी दिनों में कृषि विज्ञान केंद्र, धमतरी में मखाना के कटाई-पश्चात प्रबंधन का वैज्ञानिक प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें संग्रहण के बाद की प्रक्रियाओं, प्रसंस्करण और गुणवत्ता प्रबंधन से संबंधित तकनीकी जानकारी देने पर जोर रहेगा।

प्रशिक्षण का उद्देश्य महिलाओं को मखाना उत्पादन की पूरी प्रक्रिया समझाना है, ताकि वे इस गतिविधि को बेहतर ढंग से संचालित कर सकें। उत्पादन और प्रसंस्करण की जानकारी मिलने से समूहों को भविष्य में अपने स्तर पर स्वरोजगार विकसित करने में मदद मिल सकती है। साथ ही, गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने की क्षमता बढ़ने से बाजार में अपनी पहचान बनाने के अवसर भी मिलेंगे।

प्राकृतिक संसाधनों से बढ़ेगी ग्रामीण आजीविका

कलेक्टर धमतरी ने कहा कि जिले में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग करते हुए किसानों की आय बढ़ाने और महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मखाना की खेती इस दिशा में एक अच्छा विकल्प बन सकती है।

उन्होंने उत्पादन के साथ वैज्ञानिक तकनीक, प्रसंस्करण, गुणवत्ता और बाजार से जुड़ाव पर विशेष ध्यान देने की बात कही, ताकि ग्रामीण महिलाओं को इस पहल का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इससे स्पष्ट है कि मखाना उत्पादन को केवल खेती की एक गतिविधि के रूप में नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के अवसर के रूप में भी देखा जा रहा है।

मखाना की खेती से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम

धमतरी जिले में मखाना उत्पादन की शुरुआत ग्रामीण महिलाओं के लिए संभावनाओं का नया द्वार खोल रही है। छाती और डांडेसरा की महिला स्व-सहायता समूहों द्वारा 29 एकड़ में उत्पादित मखाना का संग्रहण शुरू होना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि, इस पहल से महिलाओं की वास्तविक आमदनी कितनी बढ़ेगी, यह उत्पादन, प्रसंस्करण लागत, बाजार मूल्य और बिक्री की व्यवस्था पर निर्भर करेगा।

यदि महिलाओं को नियमित तकनीकी प्रशिक्षण, उचित प्रसंस्करण सुविधाएं और बाजार तक बेहतर पहुंच मिलती है, तो मखाना की खेती उनके लिए टिकाऊ स्वरोजगार का माध्यम बन सकती है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ महिलाओं की आर्थिक भागीदारी भी बढ़ने की संभावना है।

धमतरी की यह पहल संदेश देती है कि सही मार्गदर्शन, सामूहिक प्रयास और उपलब्ध संसाधनों के बेहतर उपयोग से ग्रामीण महिलाएं खेती के नए क्षेत्रों में भी अपनी पहचान बना सकती हैं। तालाबों में तैयार हो रही मखाना की फसल अब उनके आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीद बनकर सामने आ रही है।

पत्थरों को आकार देने वाले मूर्तिकार की बेटी के सपनों को मिला नया सहारा

मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से ऐश्वर्या को मिली 20 हजार रुपये की मदद, पिता की चिंता हुई कम



धमतरी। पत्थरों को तराशकर सुंदर मूर्तियां बनाने वाले एक मेहनतकश पिता के लिए उसकी बेटियों की शिक्षा और बेहतर भविष्य सबसे बड़ा सपना है। अपनी कला और मेहनत के दम पर परिवार का भरण-पोषण करने वाले मूर्तिकार मनोज कुमार गंगबेर की इसी उम्मीद को छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से नई मजबूती मिली है। धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी निवासी मनोज कुमार गंगबेर की बेटी ऐश्वर्या को योजना के तहत 20 हजार रुपये की आर्थिक सहायता मिली है। इस सहयोग से परिवार को आर्थिक राहत मिली है और ऐश्वर्या की पढ़ाई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने की राह आसान हुई है।

सीमित आमदनी में बेटियों को पढ़ाने का संकल्प

ग्राम लोहरसी निवासी श्री मनोज कुमार गंगबेर पेशे से मूर्तिकार हैं। पत्थरों को अपने हुनर से आकर्षक मूर्तियों में ढालना उनकी कला के साथ-साथ परिवार की आजीविका का प्रमुख साधन भी है। मूर्तिकारी से होने वाली आमदनी

काम के ऑर्डर पर निर्भर करती है। ऐसे में परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी दोनों बेटियों की शिक्षा का खर्च उठाना उनके लिए चुनौतीपूर्ण रहा है।

आर्थिक संसाधन सीमित होने के बावजूद मनोज कुमार ने बेटियों की पढ़ाई को प्राथमिकता दी। उनकी इच्छा है कि बेटियां अच्छी शिक्षा प्राप्त करें, आत्मनिर्भर बनें और अपने जीवन में सफलता हासिल करें। इसी उद्देश्य से वे अपनी मेहनत की कमाई से परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए बेटियों के भविष्य को संवारने में जुटे हैं।

सरकारी योजना से मिली आर्थिक मदद

इसी दौरान श्रम विभाग में पंजीकृत श्रमिक मनोज कुमार गंगबेर को छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना की जानकारी मिली। उन्होंने योजना के तहत अपनी बेटी ऐश्वर्या के लिए आवेदन किया। आवश्यक दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता संबंधी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ऐश्वर्या के बैंक खाते में 20 हजार रुपये की सहायता राशि सीधे अंतरित की गई।

योजना से मिली इस आर्थिक सहायता ने परिवार को

राहत दी है। अब ऐश्वर्या की शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में इस राशि का उपयोग किया जा सकेगा। इससे पिता पर आर्थिक दबाव कुछ कम हुआ है और उन्हें बेटी की पढ़ाई तथा भविष्य को लेकर अधिक भरोसा मिला है।

बेटी की पढ़ाई को लेकर पिता की चिंता हुई कम

मनोज कुमार गंगबेर के लिए यह सहायता केवल आर्थिक सहयोग नहीं, बल्कि उनकी मेहनत और उम्मीदों को मिला संबल भी है। जिस पिता के हाथ पत्थरों को सुंदर आकार देते हैं, वही पिता अपनी बेटियों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करता है। परिवार की सीमित आमदनी के बीच शिक्षा का खर्च उठाना आसान नहीं था, लेकिन शासन की योजना से मिली सहायता ने उनकी चिंता को कुछ कम किया है।

मनोज कुमार का मानना है कि बेटियों को अच्छी शिक्षा और आगे बढ़ने के अवसर मिलना जरूरी है। आर्थिक कठिनाइयों के बावजूद वे चाहते हैं कि उनकी बेटियां अपने पैरों पर खड़ी हों और अपने सपनों को साकार करें।

मुख्यमंत्री और श्रम विभाग के प्रति जताया आभार

योजना से लाभान्वित होने पर मनोज कुमार गंगबेर ने खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि मूर्तिकारी से होने वाली सीमित आमदनी में परिवार चलाने के साथ बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना कठिन होता है। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत उनकी बेटी ऐश्वर्या को 20 हजार रुपये मिले हैं। इससे उसकी शिक्षा संबंधी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी और परिवार की चिंता भी कम हुई है।

उन्होंने इस सहयोग के लिए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय और श्रम विभाग के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

आत्मनिर्भर भविष्य की ओर बढ़ना चाहती है ऐश्वर्या

ऐश्वर्या की कहानी उन श्रमिक परिवारों की उम्मीदों को सामने लाती है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने बच्चों को बेहतर शिक्षा देकर उनका भविष्य संवारना चाहते हैं। आर्थिक सहायता मिलने से ऐश्वर्या को अपनी पढ़ाई जारी रखने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिला है। अब वह अपनी मेहनत और लगन से अपने सपनों को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहती है।

श्रमिक परिवारों के सशक्तिकरण में योजनाओं की भूमिका

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा श्रमिक परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना का उद्देश्य पात्र हितग्राहियों को आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराकर बेटियों के बेहतर भविष्य की दिशा में सहायता प्रदान करना है।

धमतरी जिले के ग्राम लोहरसी की ऐश्वर्या की यह कहानी बताती है कि समय पर मिलने वाली आर्थिक सहायता किसी परिवार की चिंता कम करने के साथ बच्चों के सपनों को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। एक ओर पिता अपनी कला और मेहनत से परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, तो दूसरी ओर शासन की योजना से मिले सहयोग ने बेटी की शिक्षा की राह को और मजबूत किया है।

यह केवल 20 हजार रुपये की सहायता की कहानी नहीं, बल्कि एक मेहनतकश पिता के विश्वास, बेटी की शिक्षा और आत्मनिर्भर भविष्य की उम्मीदों को नई ताकत मिलने की प्रेरक सक्सेस स्टोरी है।

क्या बिकने वाला है भिलाई स्टील प्लांट?

भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव ने उठाए सवाल, भाजपा ने मांगे सबूत; मंत्रालय और प्रबंधन ने किया खंडन



• राकेश निर्मलकर, संवाददाता, रायपुर

रायपुर/भिलाई। छत्तीसगढ़ की औद्योगिक पहचान माने जाने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) को बेचे जाने की चर्चाओं ने प्रदेश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने संयंत्र के संभावित निजीकरण को लेकर सवाल उठाए हैं। दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के दावों पर सवाल खड़े करते हुए प्रमाण सार्वजनिक करने की मांग की है। इस बीच, इस्पात मंत्रालय और भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने बिक्री की योजना से जुड़ी खबरों को असत्य और भ्रामक बताया है।

18 अक्टूबर 2026 को संयंत्र प्रबंधन की ओर से जारी स्पष्टीकरण के बाद भी इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर भिलाई स्टील प्लांट को बेचने की चर्चा कैसे शुरू हुई, कांग्रेस के आरोप क्या हैं और सरकार तथा प्रबंधन का इस पर क्या कहना है?

भूपेश बघेल ने अदाणी के संभावित दौर पर उठाए सवाल

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेश बघेल ने 14 अक्टूबर को सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर भिलाई स्टील प्लांट में अदाणी समूह के संभावित दौर को लेकर सवाल उठाए थे।

बघेल ने आशंका जताई कि अदाणी समूह का संयंत्र में संभावित दौरा किसी बड़े उद्देश्य से जुड़ा हो सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नजर अब भिलाई स्टील प्लांट पर है और इसे बेचने की कोशिश की जा सकती है।

बघेल ने भिलाई स्टील प्लांट को छत्तीसगढ़ की पहचान बताते हुए कहा कि प्रदेश की जनता इसे किसी भी कीमत पर बिकने नहीं देगी। उन्होंने भाजपा नेताओं से भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने की बात कही।

इसके बाद 22 अक्टूबर को बघेल ने संयंत्र प्रबंधन के खंडन पर भी सवाल उठाए। उन्होंने पूछा कि प्रबंधन के जनसंपर्क विभाग को बिक्री की खबरों का खंडन जारी करने का अधिकार किसने दिया। उन्होंने यह भी सवाल किया कि क्या यह बयान भारत सरकार की अनुमति से जारी किया गया है।

बघेल ने आरोप लगाया कि अदाणी समूह की नजर संयंत्र की रेल मिल पर भी हो सकती है। हालांकि, ये उनके आरोप और आशंकाएं हैं; उपलब्ध रिपोर्टों में संयंत्र की बिक्री या रेल मिल के अधिग्रहण की पुष्टि करने वाला कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है।

देवेंद्र यादव ने प्रबंधन से पूछा- 10 हजार लोगों को घर खाली करने का नोटिस क्यों?

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने भी भिलाई स्टील प्लांट को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने संयंत्र प्रबंधन के उस बयान पर सवाल उठाए, जिसमें बिक्री की खबरों को भ्रामक बताया गया था।

22 अक्टूबर को प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक, यादव ने सवाल किया कि यदि संयंत्र को बेचने की कोई योजना नहीं है, तो लगभग 10 हजार रहवासियों को घर खाली करने के नोटिस क्यों दिए गए हैं।

यादव ने इस कार्रवाई को लेकर प्रबंधन से स्पष्टीकरण मांगा और संयंत्र तथा उससे जुड़ी बसाहट के भविष्य पर चिंता जताई। उन्होंने निजीकरण की आशंका के बीच संयंत्र को बचाने के लिए संघर्ष करने की बात भी कही।

हालांकि, घर खाली करने के कथित नोटिस और संयंत्र की बिक्री के बीच कोई प्रत्यक्ष संबंध स्थापित करने वाला

दस्तावेज उपलब्ध रिपोर्टों में सामने नहीं आया है। इसलिए इन दोनों विषयों को अलग-अलग तथ्यों के आधार पर देखना जरूरी है।

भाजपा का जवाब-दावा है तो प्रमाण सामने लाइए

भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री की चर्चाओं पर भाजपा नेताओं ने कांग्रेस के आरोपों को चुनौती दी है।

भिलाई नगर के भाजपा विधायक रिकेश सेन ने भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव से पूछा कि यदि उनके पास संयंत्र को अदाणी समूह या किसी निजी कंपनी को बेचे जाने से संबंधित जानकारी है, तो उसके प्रमाण सार्वजनिक किए जाएं।

सेन ने भिलाई स्टील प्लांट को शहर के सम्मान और पहचान से जुड़ा बताते हुए कहा कि यदि कभी संयंत्र के निजीकरण की कोशिश होती है, तो वह इसका विरोध करेंगे

और धरने पर बैठेंगे।

भाजपा की राज्यसभा सांसद लक्ष्मी वर्मा ने भी बिक्री की चर्चाओं को बेबुनियाद बताया और कांग्रेस पर राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। भाजपा नेताओं का कहना है कि संयंत्र को बेचने के दावों को प्रमाणों के साथ सामने रखा जाना चाहिए।

इस प्रकार, जहां कांग्रेस संभावित निजीकरण को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं भाजपा का जोर इन आरोपों के समर्थन में प्रमाण पेश करने पर है।

इस्पात मंत्रालय ने क्या कहा?

भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री की चर्चाओं के बीच इस्पात मंत्रालय ने 17 अक्टूबर को अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर स्पष्टीकरण जारी किया।

मंत्रालय ने समाचार पत्रों में प्रकाशित उन खबरों का खंडन किया, जिनमें सरकार की ओर से भिलाई स्टील प्लांट को बेचने की तैयारी किए जाने की आशंका जताई गई थी। मंत्रालय ने इस दावे को गलत बताया और लोगों से आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने का आग्रह किया।

प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की फैक्ट चेक इकाई ने भी संबंधित दावों को गलत और निराधार बताया।

मंत्रालय के इस स्पष्टीकरण के बाद फिलहाल उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार, भिलाई स्टील प्लांट की बिक्री की कोई घोषित योजना सामने नहीं आई है।

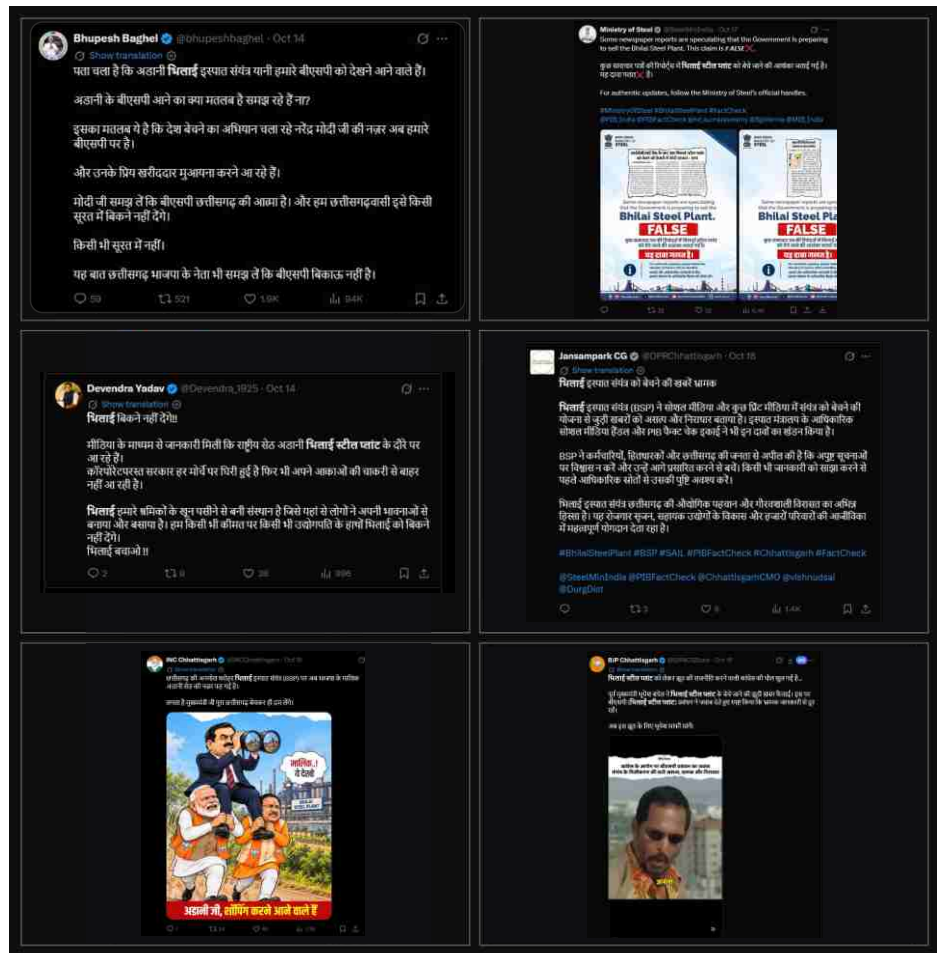
भिलाई स्टील प्लांट प्रबंधन का पक्ष

18 अक्टूबर को भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन ने भी बिक्री की योजना से जुड़ी खबरों को असत्य और भ्रामक बताया।

प्रबंधन के मुताबिक, भिलाई स्टील प्लांट सार्वजनिक क्षेत्र की स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) की प्रमुख इकाई है। संयंत्र देश के इस्पात क्षेत्र की प्रगति, औद्योगिक विकास और रोजगार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

प्रबंधन ने कहा कि बीएसपी केवल एक औद्योगिक प्रतिष्ठान नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ की पहचान, गौरव और औद्योगिक विरासत का हिस्सा है। इससे हजारों परिवारों की आजीविका जुड़ी हुई है और यह सहायक उद्योगों को भी सहयोग देता है।

प्रबंधन ने कर्मचारियों, श्रमिक संगठनों, संबंधित पक्षों और प्रदेश की जनता से अपील की कि वे अप्रुष्ट सूचनाओं पर विश्वास न करें और ऐसी खबरों को बिना पुष्टि के आगे प्रसारित करने से बचें।



डिजिटल इंडिया में 'डिजिटल गुलामी', प्रदेशभर में 50 दिनों में 5220 ठगी के मामले



• चंचल द्विवेदी, संवाददाता, रायपुर

देश-दुनिया में साइबर क्राइम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे अब छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं रहा, छत्तीसगढ़ में आये दिन ऐसे मामले सामने आते हैं जहां पर लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लेकर पूरे प्रदेश में साइबर ठगों ने आतंक मचा रखा है। पुलिस कहती है कि हमने करोड़ों लोगों को पढ़ा दिया, समझा दिया... लेकिन ज़मीनी हकीकत यह है कि ठग हर रोज़ किसी न किसी घर की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं।

साइबर क्राइम की इस आंधी को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस ने 15 अगस्त से 2 अक्टूबर के बीच पूरे 50 दिनों का महा-जागरूकता अभियान चलाया था। पुलिस का सीना चौड़ा करके दावा था कि इस दौरान प्रदेशभर में करीब 2 करोड़ लोगों तक साइबर सुरक्षा का संदेश पहुंचाया गया। अकेले रायपुर कमिश्नरेट में 4.12 लाख और ग्रामीण इलाकों में 50 हजार से ज़्यादा लोगों को पढ़ाया गया कि बेटा ऑनलाइन ठगों से बचकर रहना। लेकिन नतीजा क्या रहा? इन 50 दिनों के भीतर ही

नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर प्रदेशभर से 5220 शिकायतें दर्ज हो गईं और ज़रा रायपुर का हाल देखिए इन 50 दिनों में सिर्फ रायपुर से 955 से ज़्यादा शिकायतें पहुंच गईं। रायपुर में हर साल 4,000 से ज़्यादा शिकायतें आती हैं, लेकिन मजाल है कि एफआईआर (FIR) का आंकड़ा 100-120 से ऊपर निकल जाए, यानी ज़्यादातर लोग ठगाकर सिर्फ थाने के चक्कर ही काटते रह जाते हैं। पुलिस की क्लासें फेल क्यों हो रही हैं, इसे इन दो खौफनाक मामलों से समझिए। ठगों ने अब ऐसा 'साइबर टॉर्चर' शुरू कर दिया है कि इंसान पुलिस के पास जाने से पहले खुद ही अपनी तिजोरी खोल देता है -

1. रीता खन्ना 62 वर्ष, नर्मदापारा -

इस बुजुर्ग महिला के पास एक फोन आता है। फोन करने वाला खुद को महाराष्ट्र का NIA अधिकारी विक्रम सिंह बताता है। वो कहता है कि आप मनी लॉन्ड्रिंग में फंस चुकी हैं, इसके बाद महिला को लगातार 5 दिनों तक वीडियो कॉल पर 'डिजिटल अरेस्ट' करके रखा गया। डर के मारे कांपती हुई इस महिला ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी से 7 लाख रुपए ठगों के हवाले कर दिए।

2. देवसिंह साहू 64 वर्ष, उरकुरा -

यह मामला तो और भी दहला देने वाला है। एक कारोबारी देवसिंह साहू और उनकी पत्नी को फर्जी CBI और IPS अफसर बनकर डराया गया कि करोड़ों के फर्जीवाड़े में उनका

नाम आ गया है। 44 दिनों तक उन्हें मानसिक प्रताड़ना दी गई, डर ऐसा कि अपनी ज़मानत और जान बचाने के लिए उन्हें अपने घर के गहने तक बेचने पड़े और 8.50 लाख रुपए गंवाने पड़े।

3. शांतिर APK फाइल का खेल -

सिर्फ फोन कॉल ही नहीं, एक कारोबारी को शादी के नेवता के नाम पर और एक रिटायर बैंककर्मी को पेंशन कार्ड अपडेट करने के बहाने व्हाट्सएप पर एक छोटी सी APK फाइल भेजी गई। जैसे ही उन्होंने उस पर क्लिक किया, फोन का सारा डेटा और बैंक अकाउंट खाली हो गए एक झटके में 8.15 लाख रुपए गायब।

जानकारों का मानना है कि पुलिस जब भी कार्रवाई करती है, वह सिर्फ उन छोटे-मोटे लोगों तक पहुंच पाती है जिन्होंने अपने बैंक खाते (Mule Accounts) किराए पर दिए थे। असली मास्टरमाइंड तो सात समंदर पार या देश के किसी कोने में बैठकर रिमोट से पूरा खेल चला रहे हैं। जब तक विदेशी नेटवर्क, डिजिटल साक्ष्यों की बारीकी और एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर नहीं होगा, तब तक इस दीमक को रोकना मुश्किल है।

पुलिस लाख जागरूकता अभियान चला ले, जब तक आप खुद ध्यान नहीं देंगे, तब तक कोई आपको नहीं बचा सकता। कोई अनजान वीडियो कॉल आए, कोई खुद को NIA-CBI बताए या कोई APK फाइल भेजे - तुरंत समझ जाओ कि सामने वाला ठग है।

छत्तीसगढ़ में रिश्तखोरी में कौन-सा विभाग सबसे आगे?

• आरती बेनिया, संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ में रिश्तखोरी के मामलों को लेकर सामने आए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2021 से मई 2026 तक के आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे आगे है। यहां एसडीओ से लेकर कोटवार तक के नाम रिश्तखोरी के मामलों में सामने आए हैं।

193 सरकारी कर्मचारी गिरफ्तार

आंकड़ों के मुताबिक, बीते पांच वर्षों में रिश्त लेने के आरोप में 193 अधिकारी-कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में कुल 51.60 लाख रुपये से अधिक की रिश्त लिए जाने की जानकारी सामने आई है।

वर्षवार आंकड़ों पर नजर डालें तो 2023 में कोई मामला दर्ज नहीं हुआ। वहीं, 2024 में दर्ज 44 मामलों में 57 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। साल 2025 में 60 मामलों में 71 लोगों की गिरफ्तारी हुई। 2026 में मई तक 24 मामलों में 36 लोग रिश्तखोरी के आरोप में पकड़े गए।

राजस्व विभाग पहले नंबर पर

विभागवार आंकड़ों में राजस्व विभाग सबसे ऊपर है। यहां 56 ट्रेप मामलों में 67 लोग पकड़े गए। इनमें एसडीओ से लेकर कोटवार तक शामिल हैं।

स्कूल शिक्षा विभाग दूसरे नंबर पर रहा। यहां 20 मामलों में 25 अधिकारी-कर्मचारी पकड़े गए। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में 14 मामलों में 15 और पुलिस विभाग में 10 मामलों में 13 रिश्तखोरी के आरोपी पकड़े गए। इनमें टीआई से लेकर सिपाही तक शामिल हैं।

वहीं, परिवहन विभाग में पिछले पांच वर्षों के दौरान रिश्तखोरी का सिर्फ एक मामला दर्ज होने की जानकारी दी गई है।

ये आंकड़े सरकारी विभागों में रिश्तखोरी के खिलाफ कार्रवाई की तस्वीर दिखाते हैं। अब सवाल है कि ऐसे मामलों पर रोक लगाने के लिए व्यवस्था में कितने बदलाव होंगे।

एन्टी करप्शन ब्यूरो, छत्तीसगढ़, रायपुर				
पिछले 5 वर्षों में एसीबी में पंजीबद्ध ट्रेप प्रकरण				
वर्ष	ट्रेप प्रकरणों की संख्या	गिरफ्तार (शासकीय अधिकारी / कर्मचारी)	रिश्वत राशि (रुपये में)	सजा
2021	13	14	247500	2
2022	13	18	382000	2
2023	00	00	00	0
2024	44	57	1152000	2
2025	60	71	2391540	0
2026 (दिनांक 28.05.2026 तक)	24	33	994500	0
योग	154	193	5167540	06

कौन थे 'धरती आबा' बिरसा मुंडा, जिनके नाम से कांपते थे अंग्रेज?



• चंचल द्विवेदी, संवाददाता, रायपुर

15 नवंबर को हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी और आदिवासियों के प्रिय 'धरती आबा' कहे जाने वाले भगवान बिरसा मुंडा की जयंती आ रही है, जिन्हें भारत के आदिवासी भगवान की तरह पूजते हैं। 15 नवंबर 1875 को झारखंड के सालगा गांव में एक गरीब किसान परिवार में जन्मे बिरसा मुंडा के पिता का नाम सुगना पुर्ती और माता

का नाम करमी पुर्ती था। सालगा गांव से शुरूआती पढ़ाई पूरी करने के बाद वे चाईबासा के गोस्नर इवेंजेलिकल लुथरन चर्च विद्यालय में पढ़ने गए। उनका बचपन संघर्षों के बीच बीता, लेकिन जैसे-जैसे वे बड़े हुए, उनकी सोचने-समझने और समाज को देखने की क्षमता का दायरा काफी व्यापक हो गया। 19वीं शताब्दी के अंत में जब अंग्रेजों ने आदिवासियों को उनके जल-जंगल-जमीन और प्राकृतिक



संसाधनों से बेदखल करना शुरू किया और मिशनरियों ने गरीबी व बीमारियों का फायदा उठाकर उनका धर्मांतरण करना चाहा, तब युवा बिरसा ने इस कुचक्र को गहराई से समझा। उन्होंने आदिवासियों को यह सिखाया कि चेचक और हैजा जैसी बीमारियों कोई ईश्वरीय प्रकोप नहीं, बल्कि इनसे लड़ा जा सकता है। उन्होंने लोगों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने और मिशनरियों के बहकावे में न आने की प्रेरणा

दी। आदिवासियों को संगठित कर अंग्रेजों की दमनकारी नीतियों और जमींदारी प्रथा के खिलाफ उन्होंने 'उलगुलान' (महाविद्रोह) का बिगुल फूंक दिया। जल, जंगल, जमीन और आदिवासी अस्मिता की रक्षा के लिए किया गया उनका यह संघर्ष इतिहास में अमर हो गया और वे केवल 25 वर्ष के छोटे से जीवनकाल में ही 'धरती आबा' के रूप में भारत के जन-जन के दिल में बस गए।

कैबिनेट के बैठक में बड़ा सन्देश!! क्यों मंत्रियों की लाइन में बैठे दोनों डिप्टी CM!

• आरती बेनिया, संवाददाता, रायपुर

अनुशासन का संदेश या प्रोटोकॉल की वापसी कैबिनेट बैठक में नई व्यवस्था चर्चा का विषय

छत्तीसगढ़ भाजपा की नई प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के दो दिवसीय दौरे के ठीक बाद, लगभग 14 घंटे के अंतराल में 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास में साय कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक की जो तस्वीर सामने आई, उसने राजनीतिक गलियारों में सबको हैरान कर दिया है। सरकार गठन के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि कैबिनेट की इस गोपनीय बैठक में दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के अगल-बगल नहीं, बल्कि आम मंत्रियों की कतार में बैठे नजर आए।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के ठीक बगल से दोनों उपमुख्यमंत्रियों-अरुण साव और विजय शर्मा की सीट बदलने को लेकर सत्ता और संगठन के भीतर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। राजनीतिक हलकों में कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या अचानक बदला गया यह सीटिंग अरेंजमेंट नई प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी के कड़े तेवरों और सख्त अनुशासन का सीधा असर है, या फिर इसके पीछे कोई प्रशासनिक नियम है।

स्मृति ईरानी के लौटते ही बदल गई साय कैबिनेट की तस्वीर!

छत्तीसगढ़ की राजनीति में इन दिनों बदलाव की हवा बहुत तेज़ चल रही है। बीजेपी की नई प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी दो दिनों तक रायपुर में मैराथन बैठकें करने के बाद जैसे ही दिल्ली रवाना हुई, उसके ठीक बाद मुख्यमंत्री निवास में कैबिनेट की एक अहम बैठक बुलाई गई। लेकिन जब इस बैठक की तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आईं, तो हर कोई चौंक गया। तस्वीरों में साफ दिख रहा था कि कैबिनेट की



बैठक में मंत्रियों के बैठने की पूरी व्यवस्था यानी सीटिंग अरेंजमेंट बदला जा चुका था। जो दो डिप्टी सीएम हमेशा मुख्यमंत्री के साथ सबसे खास कुर्सियों पर बैठते थे, वे इस बार बाकी मंत्रियों के साथ कतार में बैठे थे।

अब तक क्या था छत्तीसगढ़ कैबिनेट का पुराना सीटिंग पैटर्न?

बता दें कि दिसंबर 2023 में जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और दोनों उप-मुख्यमंत्रियों ने शपथ ली थी, तब से लेकर अब तक

छत्तीसगढ़ में जितनी भी कैबिनेट बैठकें हुईं, उनका एक तय पैटर्न था। मुख्यमंत्री के एक तरफ डिप्टी सीएम अरुण साव बैठते थे और दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा बैठते थे।

मंत्रियों की लाइन में क्यों बैठे दोनों डिप्टी सीएम? क्या कहता है नियम?

बड़ा सवाल यह है कि आखिर दोनों डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री के बगल में ना बैठकर आखिर मंत्रियों की लाइन में क्यों बैठे? इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियम है। इसके पीछे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक नियम है। नियम के मुताबिक, कैबिनेट का पदेन सचिव राज्य का मुख्य सचिव होता है, जो कैबिनेट मीटिंग के सभी एजेंडों को प्रस्तुत करने वाला सबसे बड़ा मुख्य अधिकारी होता है। किसी भी राज्य की कैबिनेट बैठक का यह सख्त प्रोटोकॉल है कि मुख्य सचिव को हमेशा मुख्यमंत्री के ठीक बगल में बैठना चाहिए ताकि प्रशासनिक काम आसानी से हो सके।

स्मृति ईरानी के कड़े तेवरों का असर या 'भैया वाली राजनीति' पर ब्रेक?

राजनैतिक गलियारों में इस बदलाव को सीधे तौर पर स्मृति ईरानी के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान स्मृति ईरानी ने साफ़ कर दिया था कि सरकार और संगठन में किसी भी तरह का वीआईपी कल्चर या दिखावा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मंत्रियों को सरकारी सुख-सुविधाओं से दूर रहने और सीधे ज़मीन पर काम करने की नसीहत दी थी। विश्लेषकों का मानना है कि इस बदलाव के ज़रिए यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब सरकार में सिर्फ और सिर्फ काम और नियमों के मुताबिक ही परिणाम तय होंगे, और किसी भी तरह की 'प्रेशर या दिखावे की राजनीति' पर पूरी तरह से ब्रेक लगा दिया गया है।

छत्तीसगढ़ रेलवे लाइन में होने जा रहा बड़ा बदलाव - बस्तर से लेकर राजधानी तक बिछेगा रेल लाइनों का महाजाल

• चंचल द्विवेदी, संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर और परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह बदलने के लिए रेलवे के पहिये अब पूरी गति से दौड़ने लगे हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की मौजूदगी और केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की वर्चुअल उपस्थिति में जो नई सौगातें मिली हैं, उन्होंने राज्य के अंदरूनी इलाकों में उम्मीदों की नई रोशनी जगा दी है। आइए जानते हैं कि बस्तर से लेकर मध्य छत्तीसगढ़ तक कौन-कौन सी नई रेल लाइनें सफर आसान करने आ रही हैं, और इसके साथ क्या अच्छे और बुरे बदलाव देखने को मिलेंगे।

विकास की इस दौड़ में सबसे बड़ी राहत उन इलाकों को मिली है, जो सदियों से रेल सुविधाओं से कटे हुए थे

ताड़ोकी-रावघाट रेल खंड (95 किमी) - लगभग 1,628 करोड़ रुपये की भारी-भरकम लागत से तैयार दिल्लीराजहरा-रावघाट परियोजना के अंतिम चरण में ताड़ोकी से रावघाट तक का 95 किलोमीटर लंबा हिस्सा अब पूरी तरह आकार ले चुका है। इसके शुरू होने से बस्तर अंचल के रावघाट क्षेत्र तक यात्री ट्रेन सेवा पहुंच गई है। यह सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि भिलाई इस्पात संयंत्र तक लौह अयस्क पहुंचाने के लिए भी एक गेम-चेंजर साबित होने वाला है।

अभनपुर-कुरुद ब्रॉडगेज लाइन (22 किमी) - राजधानी रायपुर के बिल्कुल करीब बसी कुरुद विधानसभा और आसपास के क्षेत्र के लिए 22 किलोमीटर लंबी नई ब्रॉडगेज लाइन किसी वरदान से कम नहीं है। इसके शुरू होने से दैनिक यात्रियों, छात्रों, किसानों और व्यापारियों का रायपुर आना-जाना बेहद सुगम और आरामदायक हो गया है।

अब बात करते हैं उस सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की, जो



छत्तीसगढ़ के नक्शे को पूरी तरह बदलकर रख देगा। हम बात कर रहे हैं खरसिया-नया रायपुर-परमलकसा नई डबल रेल लाइन परियोजना की। लगभग 278 किलोमीटर लंबी इस विशाल डबल रेल लाइन परियोजना पर करीब 7,854 करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं।

यह रेल लाइन मुख्य तौर पर रायगढ़ (खरसिया) से शुरू होकर सक्ति, जांजगीर-चांपा, बलौदाबाजार-भाटापारा, बिलासपुर, रायपुर (खरोरा और नया रायपुर), दुर्ग होते हुए राजनांदगांव (परमलकसा) तक जाएगी।

इसके अलावा, कटघोरा से डोंगरगढ़ के बीच लगभग 294.5 किलोमीटर लंबी विद्युतीकृत ब्रॉडगेज लाइन (लागत करीब 5,950 करोड़ रुपये) कोरबा से शुरू होकर मुंगेली, कबीरधाम और राजनांदगांव के रास्तों को जोड़ेगी। साथ ही, महाराष्ट्र के गढ़चिरोली से बीजापुर होते हुए बचेली तक प्रस्तावित 490 किलोमीटर लंबी रेल लाइन और कोरबा से अंबिकापुर के बीच 180 किलोमीटर लंबी

नई रेल लाइन का काम भी पाइपलाइन में है।

इन सभी विशाल परियोजनाओं का दायरा बहुत बड़ा है और इनके रास्ते में दुर्गम जंगल, नदियां और पहाड़ आते हैं। हालांकि रावघाट और कुरुद के कुछ हिस्से शुरू हो चुके हैं, लेकिन खरसिया-परमलकसा और कटघोरा-डोंगरगढ़ जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स को पूरी तरह जमीन पर उतरने और पटरियां बिचने में अगले 4 से 7 साल या उससे अधिक का समय लग सकता है, क्योंकि इसमें विस्तृत सर्वे, पर्यावरण मंजूरी और जमीन अधिग्रहण की लंबी प्रक्रिया शामिल है।

जब इन तमाम रेल पटरियों का जाल छत्तीसगढ़ के चप्पे-चप्पे पर बिछेगा, तो लोगों की जिंदगी में एक तरफ जहां खुशहाली और तरक्की के नए द्वार खुलेंगे, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर चुनौतियाँ भी सामने आएंगी।

सकारात्मक प्रभाव - निर्माण कार्य के दौरान स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे।

छोटे कारोबारियों, होटलों और ट्रांसपोर्ट सेक्टर को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा।

किसानों के उत्पाद आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंच सकेंगे।

सफर सस्ता, सुरक्षित और तेज होने से बस्तर और सरगुजा जैसे खूबसूरत लेकिन दुर्गम इलाकों में पर्यटकों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे टूरिज्म सेक्टर को नई पहचान मिलेगी।

चुनौतियाँ और संकट - पटरियां बिछाने और मार्ग तैयार करने के लिए हजारों-लाखों पेड़ काटने पड़ेंगे, जिससे पर्यावरण और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर गहरा संकट मंडराएगा।

जिन शांत गांवों और अंचलों से ये ट्रेनें गुजरेंगी, वहां की पारंपरिक शांति, सुकून और सादगी हमेशा के लिए छिन जाएगी।

ट्रेनों की आवाज और बाहरी लोगों की हलचल से ग्रामीण जीवन का मिजाज पूरी तरह बदल जाएगा।

जमीन अधिग्रहण के चलते कई परिवारों के सामने विस्थापन का संकट भी खड़ा हो सकता है।

तो कुल मिलाकर कहें तो, छत्तीसगढ़ में बिछ रहा यह रेल लाइनों का महाजाल राज्य के विकास को एक नई रफ्तार जरूर दे रहा है, जिससे व्यापार, रोजगार और सफर के नए रास्ते खुलेंगे; लेकिन इसके साथ आने वाली पर्यावरणीय चुनौतियाँ और गांवों के शांत माहौल में होने वाले बदलाव भी आँखें मूंदने वाले नहीं हैं। विकास और प्रकृति के बीच का संतुलन ही यह तय करेगा कि यह सफर कितनी सुहानी मंजिल तक पहुँचेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन इन चुनौतियों से कैसे निपटता है और जनता के जीवन में इससे कितने सकारात्मक बदलाव आते हैं।

बॉलीवुड के दिग्गजों से छत्तीसगढ़ी गीत गवाने वाले दिलीप षडंगी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू: संघर्ष, साधना और संगीत की अनकही कहानी



• राकेश निर्मलकर, संवाददाता, रायपुर

छत्तीसगढ़ी कला और संगीत जगत में दिलीप षडंगी एक ऐसा नाम है, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। अपनी खनकती आवाज़, ठेठ छत्तीसगढ़ी गीतों और बेहतरीन लेखनी के दम पर उन्होंने न केवल प्रदेश में बल्कि पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यह उनकी ही कला का जादू था कि सोनू निगम, कुमार सानू, बाबुल सुप्रियो और अनुराधा पौडवाल जैसे बॉलीवुड के दिग्गज गायकों ने भी उनके रचे छत्तीसगढ़ी गीतों को अपनी सुरीली आवाज़ दी और वे गीत आज भी लोगों की जुबान पर कायम हैं। हाल ही में 'ठीहा छत्तीसगढ़' के विशेष कार्यक्रम में दिलीप षडंगी ने अपने जीवन, संगीत यात्रा, बॉलीवुड गायकों के साथ अपने अनुभव और आज के दौर के गीतों में आ रही गिरावट पर खुलकर बात की। पेश हैं इस खास बातचीत के प्रमुख अंश:

सवाल: कला की यह चकाचौंध वाली दुनिया है, जहाँ कई लोग आते हैं और शोहरत कमाकर नदारद हो जाते हैं। लेकिन आप आज भी प्रासंगिक हैं, इसका क्या कारण है?

जवाब: मुझे खुद नहीं मालूम कि लोग मुझसे इतना स्नेह और प्रेम क्यों करते हैं। मैं अपनी कमियों को जानता हूँ और जब भी मंच पर जाता हूँ तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर, जो लोग मुझे अपने योग्य समझते हैं, मुझे उनके योग्य बनाए रखना। मंच ही मेरी दुनिया है। जब मैं जनता के बीच होता हूँ, तो वह मेरे लिए किसी मंदिर में देवी-देवताओं के दर्शन करने जैसा होता है। शायद यही सरलता और देवी-देवताओं का आशीर्वाद है कि मुझे 52 सालों से जनता का इतना प्यार मिल रहा है।

सवाल: आप कला के क्षेत्र में सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे कलाकारों में से एक माने जाते हैं। कलाकारी के साथ पढ़ाई का यह सफर कैसे रहा?

जवाब: इंसान को जीवन भर सीखते और पढ़ते रहना चाहिए। मैंने हाल ही में 67 साल की उम्र में पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा (PGDJ) किया है। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जो पढ़ाई नहीं कर पाते, लेकिन मैं उन्हें यह संदेश देना चाहता हूँ कि उम्र या समय का बहाना मत बनाइए। आज मोबाइल और इंटरनेट का ज़माना है, आप बिना कॉलेज गए भी मोबाइल के ज़रिए बहुत कुछ सीख सकते हैं। ज्ञान होना

बहुत ज़रूरी है, मैं तो वॉकिंग करते हुए भी ईयरफोन लगाकर नई-नई चीज़ें सीखता रहता हूँ।

सवाल: आपका पहला चर्चित गाना कौन सा था और वह कैसे बना?

जवाब: मेरा पहला व्यावसायिक गाना 1991 के आसपास आया था। 'का साबुन चुपरथस गोरी' उस दौर में बहुत ज़्यादा हिट हुआ था। दरअसल, यह गाना रमेश महानंद जी के एक उड़िया गीत का छत्तीसगढ़ी रूपांतरण था। उस समय 'त्रिदेव' फिल्म का गाना 'ओए ओए' काफी चल रहा था, वहीं से कुछ धुन और शब्दों का पंच लेकर हमने इसे बनाया, जो श्रोताओं को काफी पसंद आया।

सवाल: आपने सोनू निगम जैसे दिग्गज गायक से 'छुनुर छुनुर पैरी बाजे' और 'ना धरती मा हे कोनो' जैसे सुपरहिट गीत गवाए। उन्हें कैसे राजी किया और वो अनुभव कैसा रहा?

जवाब: यह बात 2001 के आसपास की है। उस समय हम ओडिशा के कटक स्थित स्टूडियो में रिकॉर्डिंग के लिए गए थे। हमारा बजट बहुत कम था,

जबकि बड़े गायकों की फीस काफी ज़्यादा होती थी। मुझे सोनू निगम जी से अपना गीत गवाने के लिए स्टूडियो के बाहर 4 दिनों तक इंतज़ार करना पड़ा था। जब मेरा नंबर आया और सोनू निगम जी ने 'ना धरती मा हे कोनो' गाना गाया, तो वे खुद इसके बोल सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने मुझसे कहा कि "दिलीप जी, आपने बहुत बेहतरीन लिखा है।" सोनू निगम वास्तव में एक महान और ज़मीनी कलाकार हैं, जिन्होंने मेरे गीतों में अपनी जान फूंक दी।

सवाल: आपके इतने लंबे और शानदार करियर में क्या कोई ऐसा मलाल या पछतावा रहा, जो आज भी आपके दिल में हो?

जवाब: हां, दो बातें हमेशा दिल में चुभती हैं। पहला, स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी से कोई गाना गवाने का मेरा बहुत बड़ा सपना था, जो अधूरा रह गया। दूसरा, जब हम अपना सुपरहिट गीत 'नहीं मांगो मोटर गाड़ी' रिकॉर्ड कर रहे थे, तब स्टूडियो में श्रेया घोषाल जी भी आई हुई थीं, लेकिन बजट और परिस्थिति की वजह से वह गाना सोनाली वाजपेयी जी ने गाया। हालांकि, वह गाना सुपरहिट हुआ, लेकिन श्रेया घोषाल जी

जैसी महान गायिका से वो गाना न गवा पाने का अफ़सोस आज भी होता है।

सवाल: आजकल के गीतों में द्विअर्थी (Double Meaning), गाली-गलौज और हिंसा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, एक वरिष्ठ कलाकार के रूप में आप इस पर क्या कहेंगे?

जवाब: मैं इस बात का सख्त विरोध करता हूँ। द्विअर्थी और अश्लील गाने हमारी कला, संस्कृति और हमारी नई पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। कला का काम समाज में सकारात्मक चेतना जगाना है। मेरी सभी युवा कलाकारों, गायकों और फिल्म निर्माताओं से हाथ जोड़कर विनती है कि गीतों और फिल्मों में हिंसा व गालियों का इस्तेमाल न करें। यह बहुत ही गलत चलन है। हमें समाज के प्रति अपनी ज़िम्मेदारी समझनी चाहिए, ताकि जब हम बूढ़े हों तो गर्व से कह सकें कि हमने अपने समाज को और अपनी कला को कुछ सकारात्मक दिया है। नकारात्मकता फैलाकर कोई भी सच्चा कलाकार नहीं बन सकता।



धनतेरस ले भाई दूज तक 5 दिन के महापरब, घर-घर म बगरही सुख-समृद्धि अउ श्रद्धा के अंजोर

पांचों परब के खास बात, तिथि अउ सुभ मूहुरत



• **शशिकला साहू**, संवाददाता, रायपुर

भारत म देवारी सिर्फ एक दिन के तिहार नो हरय, भल्कू एहा श्रद्धा, संस्कृति, अउ परंपरा के पांच दिन के महापरब आय। धनतेरस ले सुरु होके नरक चतुरदसी, देवारी (लछमी पूजा), गोबरधन पूजा अउ भाई दूज तक चले वाला ए तिहार ह जिनगी म अंजोर, सुख-समृद्धि, अच्छा सुवास्थ, प्रकृति के सम्मान अउ परिवार के परेम के संदेस देथे। बछर 2026 म घलो ए पांच तिहार ला पूरा देस म अब्बड़ धूमधाम अउ उल्लास के संग मनाए जाही।

धनतेरस: सुख-समृद्धि, अच्छा सुवास्थ अउ सुभ सुरुआत के तिहार

देवारी के पहिली परब धनतेरस 6 नवंबर 2026, सुक्रार (शुक्रवार) के मनाए जाही। ए दिन भगवान धनवंतरि के परगट होए के परतीक माने जाथे। धार्मिक मानता हे कि समुंदर मंथन के बेरा म भगवान धनवंतरि ह अमरित कलस लेके परगट होए रहिन। एकरे सेती ए दिन धनतेरस के तिहार मनाए जाथे।

ए दिन भगवान धनवंतरि के संग माता लछमी, भगवान गनेस अउ कुबेर देवता के पूजा के बिसेस महत्व हे। मनखे मन ए दिन सोना-चांदी, बरतन, गाड़ी, घर या दूसर सुभ चीज बिसाथे (खरिदथे)। अइसन मानता हे कि ए दिन सुभ चीज म पइसा लगाए ले पूरा बछर सुख-समृद्धि आथे।

पंचांग के हिसाब ले कातिक कृष्ण त्रयोदशी तिथि 6 नवंबर के बिहनिया 10:30 बजे सुरु होके 7 नवंबर के बिहनिया 10:47 बजे तक रइही। धनतेरस के पूजा के सुभ मूहुरत 6 नवंबर के संझा 6:02 बजे ले 7:57 बजे तक रइही। ए बेरा म परदोस काल म बिधि-बिधान ले पूजा करना अब्बड़ सुभ माने गे हे।

नरक चतुरदसी: बुराई म अच्छाई के जीत अउ यम दीपदान के परंपरा

धनतेरस के दूसर दिन 7 नवंबर 2026, सनिच्चर के नरक चतुरदसी या छोटे देवारी मनाए जाही। एला रूप चतुरदसी अउ काली चउदस के नाव ले घलो जाने जाथे। ए तिहार बुराई म अच्छाई के जीत के संदेस देथे।

पौराणिक कथा के अनुसार ए दिन भगवान श्री कृष्ण ह अतियाचारी राकछस नरकासुर ला मार के 16100 राजकुमारी अउ माइलोगिन मन ला ओकर बंधन ले मुक्त कराए रहिन। तब ले ए दिन ला जीत अउ मुक्ति के परतीक के रूप म मनाए जाथे।

नरक चतुरदसी म सुरुज उगे के पहिली नहाए के परंपरा हे। संझा के बेरा यमराज के नाव ले दक्षिण दिसा डाहर दीया जलाए जाथे, जेला यम दीपदान कहे जाथे। मानता हे कि एकर ले अकाल मृत्यु के डर दूरिहा होथे अउ परिवार के रकछा होथे। एकर संगे-संग घर, अंगना, माई फइरका, अउ छत म दीया जलाके सकारात्मक उरजा के सुवागत करे जाथे।

देवारी: अंजोर, लछमी किरपा अउ नवा सुरुआत के महापरब

देवारी ए बछर 8 नवंबर 2026, एतवार (रविवार) के मनाए जाही। हिंदू पंचांग के हिसाब ले कातिक अमावस्या तिथि 8 नवंबर के बिहनिया 11:27 बजे सुरु होके 9 नवंबर के मंझनिया 12:31 बजे तक रइही। काबर कि परदोस काल म अमावस्या तिथि 8 नवंबर के रइही, एकरे सेती ए दिन लछमी पूजा अउ देवारी तिहार मनाए जाही।

लछमी पूजा के सुभ मूहुरत संझा 5:54 बजे ले 7:50 बजे तक रइही। ए बेरा म प्रदोष काल अउ वृषभ काल के बिसेस संजोग बने ले पूजा के महत्व अउ जादा बाढ़ गे हावय।

धार्मिक मानता के अनुसार भगवान श्रीराम 14 बछर के बनबास पूरा कर के माता सीता अउ लछमन के संग अयोध्या लहुटे रहिन। उंकर सुवागत म अयोध्या के मनखे मन दीया जला के पूरा नगर ला अंजोर कर दे रहिन। तब ले देवारी ला दीया के तिहार के रूप म मनाए जाथे।

ए दिन घर के बिसेस साफ-सफई कर के रंगोली बनाए जाथे, दीया जलाए जाथे अउ माता लछमी संग भगवान गनेस के पूजा करे जाथे। ए दिन अउ परिवार के सुख-समृद्धि अउ तरक्की के कामना करे जाथे।

छत्तीसगढ़ के अनोखा परंपरा: गउरा-गउरी पूजा

पूरा देस म देवारी म लछमी पूजा के बिसेस महत्व हे, फेर छत्तीसगढ़ म एकर संगे-संग गउरा-गउरी पूजा (गौरा-गौरी) के अनोखा परंपरा घलो निभाए जाथे। इहां भगवान सिव अउ माता पारबती के मूर्ति इसथापित कर के उंकर बिहाव के उत्सव मनाए जाथे।

परंपरा के अनुसार तरिया के माटी ले गउरा-गउरी के मूर्ति बनाए जाथे। दूसर दिन गोबरधन पूजा के बाद गाजा-बाजा के संग मूर्ति मन के बिसरजन करे जाथे। ए परंपरा छत्तीसगढ़ के सुधर लोक संस्कृति अउ समाजिक एकता के परतीक माने जाथे।

गोबरधन पूजा: प्रकृति, गउ सेवा अउ अन्नकूट के तिहार

देवारी के बाद गोबरधन पूजा के तिहार 10 नवंबर 2026, मंगलवार के मनाए जाही। एला अन्नकूट परब घलो कहे जाथे। ए तिहार भगवान श्री कृष्ण, गोबरधन पहाड़, गाय-गरुवा अउ प्रकृति के प्रति सम्मान परगट करे के संदेस देथे।

धार्मिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ह बरजवासी मन ला इंद्रदेव के पूजा छोड़ के गोबरधन पहाड़, गउ माता अउ प्रकृति के पूजा करे के संदेस दे रहिन। इंद्रदेव के गुस्सा ले बरजवासी मन ला बचाए बर श्री कृष्ण ह अपन छिनी अंगरी म गोबरधन पहाड़ ला उठाए रहिन। तब ले गोबरधन पूजा के परंपरा सुरु होइस।

ए दिन गाय के गोबर ले गोबरधन पहाड़ के चीन्हा बनाए जाथे अउ भगवान श्री कृष्ण ला अलग-अलग परकार के सात्विक पकवान के भोग लगाए जाथे।

कातिक सुक्ल प्रतिपदा तिथि 9 नवंबर के मंझनिया 12:31 बजे ले सुरु होके 10 नवंबर के मंझनिया 2 बजे तक रइही। पूजा के सुभ बेरा 10 नवंबर के बिहनिया 6:40 बजे ले 8:50 बजे तक रइही।

भाई दूज: भाई-बहिनी के अटूट परेम के तिहार

देवारी के आखिरी परब भाई दूज 11 नवंबर 2026,

बुधवार के मनाए जाही। ए तिहार भाई-बहिनी के परेम, बिसवास अउ जिनगी भर साथ निभाए के संकल्प के परतीक आय।

पौराणिक मानता के अनुसार ए दिन यमराज ह अपन बहिनी जमुना के घर गे रहिन। जमुना ह उंकर माथा म टीका लगा के सुवागत करिस। खुस होके यमराज ह बरदान दिस कि ए दिन जउन भाई अपन बहिनी ले माथा म टीका लगावाही, ओला लंबा उमर अउ सुख-समरिधि के आसीरबाद मिलही।

भाई दूज म बहिनी मन अपन भाई मन के माथा म टीका लगा के उंकर लंबा उमर, अच्छा सुवास्थ अउ तरक्की के कामना करथे। बदला म भाई ह अपन बहिनी ला उपहार देके ओकर रकछा अउ सम्मान के बचन देथे।

द्वितीया तिथि 10 नवंबर के मंझनिया 2 बजे सुरु होके 11 नवंबर के मंझनिया 3:53 बजे तक रइही। तिलक करे के सुभ मूहुरत 11 नवंबर के मंझनिया 1:10 बजे ले 3:20 बजे तक रइही।

नोट:- इहां के पंचांग के हिसाब ले मूहुरत म थोकन अंतर हो सकथे। पूजा के समय ह सहर के हिसाब ले अलग-अलग हो सकथे। एकरे सेती अपन सहर के पंचांग के हिसाब ले मूहुरत ला देख लेव।

देवारी 2026: पांच दिन के तिहार अउ सुभ मूहुरत		
तिहार	तारिख / दिन	सुभ मूहुरत
धनतेरस	6 नवम्बर 2026 (सुक्रार)	संझा 6:02 बजे ले 7:57 बजे तक
नरक चतुरदसी	7 नवम्बर 2026 (सनिच्चर)	परदोस काल म यम दीपदान अउ दीया जलाना सुभ
दीवाली (लछमी पूजा)	8 नवम्बर 2026 (एतवार)	संझा 5:54 बजे ले 7:50 बजे तक
गोबरधन पूजा	10 नवम्बर 2026 (मंगलवार)	बिहनिया 6:40 बजे ले 8:50 बजे तक
भाई दूज	11 नवम्बर 2026 (बुधवार)	मंझनिया 1:10 बजे ले 3:20 बजे तक (तिलक मूहुरत)